सत्यमेव जयते

फीजी में भारत - 2016

उत्कर्ष

वाइब्रेंट गुजरात

बिहू उत्सव – असम

आइटी हब – बैंगलुरू, कर्नाटक

ताजमहल – उत्तर प्रदेश

अंक 1

भारतीय उच्चायोग, सूवा, फीजी

अनुक्रम

- प्रस्तावना 3

भारत के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम

- स्टार्टअप इंडिया 4
- कुशल जनशक्ति का केंद्र बनेगा भारत 8
- सही संतुलन की ओर 12
- इसरो– बड़ी सोच - बड़ी उपलब्धियां 15

चार राज्य

- गुजरात– जड़ों से जुड़कर आसमान छूने का इरादा 19
- उत्तरप्रदेश– भारत का इंद्रधनुष 23
- असम– हर ओर हरियाली 28
- कर्नाटक– गंभीर वैश्विक भूमिका की ओर तेजी से अग्रसर 32

फीजी में भारत

- द्विपक्षीय संबंध 34
- मजबूत होते रिश्ते 35
- भारत– मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भागीदार 36
- आईटीईसी (आईटैक)– प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहयोग 36
- भारत परिचय कार्यक्रम (Know India Programme) 37
- भारतीय नौसैनिक जहाज– सुमित्रा 37
- अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 38
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 38
- फीजी में हिंदी– चुनौतियां और संभावनाएं 39
- प्रशांत क्षेत्र में भारत 41
- विकास में भागीदार 44

twitter @HCI_Suva facebook @IndiaInFiji

www.indianhighcommissionfiji.org

Email: hindi.suva@mea.gov.in

सूवा, फीजी में भारतीय उच्चायोग का प्रकाशन

आमुख

भारत और फीजी - विकास में साझीदार

भारत और फीजी के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत और प्रगाढ़ हैं। भारत फीजी की विकास प्रक्रिया में साझेदार है।

ये दोनों देश बहुआयामी स्तर पर अत्याधुनिक साझेदारी विकसित करने में काफी सक्रियता से लगे हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नवंबर, 2014 में किया गया फीजी दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ।

इस दौरे ने पहली बार एशिया प्रशांत द्वीपीय सहयोग संगठन 'फिपिक' की फीजी में बैठक का मार्ग प्रशस्त किया।

फीजी के प्रधानमंत्री रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) जोसाईआ वौरेंगे बाईनीमारामा ने अगस्त, 2015 में आयोजित द्वितीय फिपिक बैठक में भाग लिया।

मई, 2016 में फीजी के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों की सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई।

वर्ष 2016 में फीजी ने रियो ओलंपिक के दौरान रग्बी - 7 में स्वर्ण पदक जीता। इसी वर्ष फीजी ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली (यूएनजीए) में अध्यक्ष का पद पाया और साथ ही कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-23) में अध्यक्ष चुना गया। इस तरह से भारत और फीजी के संबंध नयी ऊंचाई को छूते गए।

भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए कौन-कौन से प्रयास किये हैं, उनकी चर्चा इस बुलेटिन में की गयी है।

फरवरी, 2016 में आये चक्रवाती तूफान विन्सटन द्वारा हुए विनाश की पीड़ा को महसूस करते हुए भारत फीजी के दुख में शामिल हुआ। भारत ने विन्सटन चक्रवाती तूफान के छठे दिन ही 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता सामग्री भेज दी। इसके साथ ही भारत ने फीजी के प्रधानमंत्री पुनर्वास राहत फंड में भी1 मिलियन डॉलर का योगदान किया।

फीजी सरकार और जनता ने भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुमित्रा के वहां पहुंचने पर व्यापक स्तर पर स्वागत किया। आईएनएस सुमित्रा की फीजी यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को नयी मजबूती प्रदान की।

विन्सटन चक्रवाती तूफान से वहां के किसानों को हुए फसल नुकसान से राहत के लिए भारत ने 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले सब्जियों के बीज भेजे, ताकि किसानों को राहत मिल सके।

इसके साथ ही भारत ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की, जिससे छोटे स्तर पर काम करने वाले उद्यमियों को उनके व्यापार के विकास में मदद मिले।

भारत 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के 2800 घरों में सौर विद्युतीकरण (जिसमें फीजी के 200 घर भी शामिल हैं) पर 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना चलाने को कृत संकल्प है। इस कार्यक्रम को राजस्थान के बेयरफुट कॉलेज के जरिए चलाया जाएगा, जहां फीजी सोलर मामाओं के प्रशिक्षण का हब बन जाएगा। इसके साथ ही भारत ने भारतीय तकनीक और आर्थिक साझेदारी (आईटैक)में 205 अल्पकालीन छात्रवृत्तियां दीं, जिसमें 30 छात्रवृत्तियां भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की हैं, जोकि पिछले साल स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के कोर्स में मानव संसाधन विकास के लिए दी गई थीं।

इसके अलावा भारतीय उच्चायोग ने कई सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जैसे आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित नृत्य/संगीत के ग्रुप, रामायण सम्मेलन, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और गिरमिट समारोह आदि। भारत विज्ञान और तकनीक, सूचना तकनीक, दवा उद्योग, मनोरंजन उद्योग, अंतरिक्ष और परमाणु उर्जा के क्षेत्र में प्रमुख देशों में से एक है।

भारत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं और उच्च प्रशिक्षित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की वजह से विश्व में बेहतर स्वास्थ्य प्रदाता देशों में से एक के रूप में उभरा है। भारत अनाज का भी निर्यातक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है और नवीनतम सुधारों के जरिए इसमें और तेजी आने की संभावना है।

हम इस अंक में भारत सरकार और चार राज्यों (गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक) द्वारा चलाये जा रहे कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री महामहिम श्री नरेंद्र मोदी फीजी के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जोसाईआ वौरेंगे बाईनीमारामा से मिलते हुए

> दोनों देश व्यापक तौर पर आधुनिक बहुआयामी साझेदारी की प्रक्रिया विकसित करने में सक्रियता से लगे हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवंबर, 2014 में किये गये फीजी दौरे ने हमारे द्विपक्षीय दोस्ताना संबंधों को और मजबूत करने में अहम योगदान दिया।

सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ये राज्य फीजी के साथ ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं और तेजी से पर्यटन और संस्कृति क्षेत्र में विकास कर रहे हैं।

ऐसी उम्मीद है कि 'फीजी में भारत-2016 उत्कर्ष' के इस वार्षिक अंक के माध्यम से भारतीय उच्चायोग द्वारा सूवा में साल 2016 में चलायी जा रही गतिविधियों व व्यापक भागीदारी के जरिये मजबूत होते द्विपक्षीय संबंध, लोगों के विचार और राय की झलक भी आपको दिखाई देगी।

- विश्वास सपकाल
उच्चायुक्त

स्टार्टअप इंडिया
सही समय पर सही विचार

भारत सरकार की इस विशिष्ट योजना की मदद से उद्यमी अपने काम को फैलाते हुए भविष्य की प्रगति को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के साथ निवेशकों और कारोबारी सुविधा प्रदान करने वालों को भी सुनहरा अवसर मिल रहा है।

स्टार्टअप इंडिया परियोजना - रोजगार का सृजन

बेरोजगारी के इस दौर में दावेदारों की तुलना में उपलब्ध रोजगार काफी कम है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी परियोजना बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यस्था होने के बावजूद बढ़ती बेरोजगारी भारत सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है।

एशिया-प्रशांत मानव विकास की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत में आने वाले 35 वर्षों में रोजगार पाना एक गंभीर चुनौती होगी।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1991 और 2013 के बीच कामगारों की जनसंख्या 300 मिलियन है, जबकि मौजूदा अर्थिक संरचना में केवल 140 मिलियन लोगों को ही रोजगार दिया जा सकता है। इस संदर्भ में सरकार की दो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं- 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप भारत' इस समस्या के समाधान की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होती हैं।

चीन से आई मंदी के परिणामस्वरूप दिख रही वैश्विक मंदी के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट साफ देखी जा सकती है। ऐसे में रोजगार सृजन के अन्य विकल्पों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत यह सुझाव आया है कि आने वाले दशक में 10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखते हैं तो इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण प्रक्षेत्र की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की जरूरत है।

इसलिए आने वाले वर्षों में 'मेक इन इंडिया' के साथ-साथ 'स्टार्टअप' जैसे कार्यक्रमों के जरिए रोजगार के नए अवसरों को बढावा दिया जा सकेगा।

नैस्कॉम का अनुमान है कि केवल सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में स्टार्टअप के जरिए वर्ष 2017 तक 800,000 नौकरियों के अवसर पैदा करने में कामयाब होंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी (बाएं से पांचवें) स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर नई दिल्ली में

> अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया में स्टार्टअप के मामले में आज भारत तीसरे पायदान पर पहुंच गया है।

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहद तेज गति से बढ़ रही है और यही कारण है कि स्टार्टअप कंपनियों के लिए भारत आकर्षण का केंद्र बन गया है। देश में मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जहां साल 2013 में 15.1 प्रतिशत थी, वहीं साल 2016 में बढ़कर 34.18 प्रतिशत हो गई। ऑनलाइन खरीदारी के मामले में भारत के उपभोक्ता पीछे नहीं हैं।

प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप प्रतिनिधियों, कुलपतियों और निवेशकों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करते हुए

वैसे देश में जहां इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहतरीन प्रतिभा कम वेतन में मौजूद है, कई कंपनियां वहां अपना कार्यालय स्थापना करने को तरजीह देंगी।

ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष की शुरूआत में नयी कंपनियों और नये निवेशकों को ध्यान में रखते हुए उनके व्यवसायिक गतिविधियों में सहयोग देने के उद्देश्य से कर दरों में प्रस्तावित छूट की जो घोषणा की गयी है, वह एक उत्प्रेरक की भूमिका निभायेगी।

इसी कड़ी में सरकार ने सस्ती और तेज पेटेंट आवेदन प्रक्रिया के साथ पेटेंट की लागत पर 80 प्रतिशत की छूट और स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का विशेष कोष बनाने का प्रस्ताव रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तीन साल के लिए टैक्स और अनुपालन निरीक्षण से छूट जैसे प्रस्ताव इस क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ावा देंगे।

भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहद तेज गति से बढ़ रही है और यही कारण है कि स्टार्टअप कंपनियों के लिए भारत आकर्षण का केंद्र बन गया है। देश में मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जहां साल 2013 में 15.1 प्रतिशत थी, वहीं साल 2016 में बढ़कर 34.18 प्रतिशत हो गई। ऑनलाइन खरीदारी के मामले भारत के उपभोक्ता पीछे नहीं हैं। केवल 2016 में आज इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने वाले 43.8 फीसदी लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी की है।

साल 2019 में यह आंकड़ा 64.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत दूसरी डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़ा है, जिसके चलते स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-कॉमर्स, आतिथ्य, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलावों के साथ ही नई नौकरियों के अवसर पैदा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में बढ़ती हुई डिजिटल खरीदारों की संख्या से उत्साहित विदेशी निवेशकों ने हाल के वर्षों में विभिन्न कैपिटल इंवेस्मेंट स्कीमों से अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया है।

न्यूयॉर्क स्थित जापान की सॉफ्टबैंक और वी वर्क जैसी साझा कार्यालय प्रदान करवाने वाली कंपनियों ने भारत को लेकर अपनी योजनाओं का ऐलान किया है।

बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुमान के मुताबिक भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग साल 2025 तक 220 अरब डालर का लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जो पिछले साल 11 अरब करोड़ डॉलर रहा था।

सॉफ्टवेयर के अलावा निवेशक गरीबों के घरों के लिए कम लागत के सौर पैनलों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सॉफ्टवेयरों के विकास में लगे स्टार्टअप की ओर अभिरूचि दिखा रहे हैं।

सामाजिक बदलावों से जुड़े स्टार्टअप में निवेश करने के लिए भारत एक विशाल बाजार प्रदान करता है। ग्रामीण भारत में लाखों लोग अभी भी बुनियादी जरूरतों जैसे पीने का पानी, शौचालय और बिजली आदि की सुविधाओं से महरूम हैं।

ग्रामीण भारत प्रतिवर्ष 8-10 फीसदी की एक स्वस्थ गति से आगे बढ़ रहा है और 2017 तक उपभोग और खपत दर में 100 अरब डॉलर तक इजाफा होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार 2018 के अंत तक सभी गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने और सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर से भारी निवेश मिल रहा है।

मोदी सरकार ने 2022 तक भारत की सौर क्षमता को पांच गुना बढ़ाकर 1,00,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। यह योजना जहां एक ओर भारत की बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा करने में अपना योगदान देगी, वहीं रोजगार के भी नए अवसर पैदा करेगी।

भारत दुनिया का सबसे युवा स्टार्टअप राष्ट्र है। यहां 70 प्रतिशत कारोबारियों की उम्र 35 वर्ष से कम है।

भारत में हर दिन लगभग तीन से चार आईटी स्टार्टअप की शुरूआत होती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत की युवा पीढ़ी की सोच में एक बदलाव साफ देखा जा सकता है। आज का युवा नौकरी चाहने वालों की तुलना में नौकरी के अवसर पैदा करने वाला बनना चाहते हैं। 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी योजनाएं देश के युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए एक आदर्श मंच है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वित्त, कारपोरेट मामलों और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली के साथ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर

> भारत दुनिया का सबसे युवा स्टार्टअप राष्ट्र है क्योंकि यहां 70 प्रतिशत कारोबारियों की उम्र 35 वर्ष से कम है। भारत में हर दिन लगभग तीन से चार आईटी-स्टार्टअप की शुरूआत होती है।

स्किल इंडिया

भारत कुशल मजदूरों के संकुल के रूप में विकसित होगा

स्किल इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों ने राज्य सरकारों के साथ अनुबंध किया है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके।

कौशल विकास (स्किल इंडिया) कार्यक्रम की शुरूआत होने के एक वर्ष बाद भी इस कार्यक्रम को काफी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य देश के युवाओं को विशेष कौशल प्रदान करना है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

अगले दशक तक10 करोड़ से ज्यादा कुशल मजदूर तैयार कर भारत बड़ी संख्या में अतिरिक्त श्रम के विकास का लक्ष्य रखता है। इस तरह से भारत वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में सफल होगा। एक आकलन के मुताबिक भारत में कुल श्रमशक्ति के मात्र 2.3 फीसदी लोग ही प्रशिक्षित हैं। जबकि तुलनात्मक रूप से यूके में 68 फीसदी और अमेरिका में 80 फीसदी श्रमिकों को प्रशिक्षण प्राप्त है।

'कौशल विकास' कार्यक्रम की शुरूआत होने के बाद से ही पूरे देश में कई प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, संस्थान और स्कूल खोले गए हैं, जो राज्य सरकारों के साथ समझौता कर बड़ी संख्या में युवाओं का पंजीयन कर रहे हैं। लगभग 55 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके तहत 23 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है।

पिछले वर्ष तक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 3000 हजार से ज्यादा हो गयी है और सरकार ने 250 से अधिक प्रशिक्षण सहयोगियों के साथ समझौता किया है।

इस अभियान का लक्ष्य 2022 तक अलग-अलग कौशल के क्षेत्र में 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है। 'कौशल विकास इंडिया' भारत में कौशल विकास की चाहत रखने वाले सभी लोगों को बुनियादी डिजिटल प्रशिक्षण के अवसर देकर डिजिटल डिवाईड अर्थात डिजिटल गैप को पाटना चाहता है।

इंटरनेट से जुड़े कौशल को प्राप्त करने में और इसके उपयोग में सुविधा इस बात से भी है कि हम इस तरह के कौशल का इस्तेमाल मोबाइल एप के जरिए भी कर सकते हैं।

जुलाई, 2016 में इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को एक वर्ष पूरा हुआ। इसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कौशल विकास और प्रशिक्षण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीय राजीव प्रताप रूडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये वादे को पूरा करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया।

नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी की उपस्थिति में श्री रूडी ने निम्नलिखित कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसके जरिए आगे का रास्ता तय किया जाएगा।

भारत को कुशल श्रम शक्ति का केंद्र बनाना है।

स्किल इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2

18 जुलाई, 2016 तक प्रशिक्षण के लिए जिन 18 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया था, उनमें से 17.93 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षित कर दिया गया। वर्ष 2015 में इस योजना का व्यय 1500 करोड़ निर्धारित था, जिसके तहत अगले साल तक 24 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। इनमें वो 10 लाख लोग भी शामिल थे, जिनके पास पहले से सीखे होने का प्रमाण था।

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत (पीएमकेवीवाई) 12,000 करोड़ रूपये का बजट दिया है, जिसके जरिए अगले चार वर्ष (2016-2020) में एक करोड़ लोगों का कौशल विकास किये जाने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत 60 लाख युवाओं को न सिर्फ प्रशिक्षित किया जाएगा, अपितु उन्हें औद्योगिक मानकों पर आधारित प्रशिक्षण नेशनल कौशल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसओएफ) के तहत दिया जाएगा। इन प्रशिक्षुओं को छूट देने के साथ ही उनके नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें खाड़ी देशों और यूरोप एवं विदेशों में अन्य जगहों पर रोजगार मिल सके।

वैसे जो छात्र बेहतर रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 'स्किल इंडिया' के एक वर्ष पूरा होने पर वर्ष 2016 तक भारत में 50 अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र खोले जाने की योजना बनाई गयी है।

पहले चरण में माननीय राष्ट्रपति श्री मुखर्जी द्वारा 15 केंद्रों की शुरूआत की जाएगी। इनकी स्थापना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के तहत की जाएगी। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) कार्यक्रम का कार्यान्यवयन ऐसे युवाओं के लिए करेगा, जो रोजगार की तलाश देश-विदेश में कर रहे हैं। पहले पंद्रह केंद्र उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलांगना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व पंजाब में स्थापित किये जाने हैं।

माननीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इंडिया स्किल्स ऑनलाइन के नाम से एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का उद्घाटन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और एनएसडीसी के तहत किया ताकि बेहतर प्रतिभाओं का चयन किया जा सके, और ये प्रतिभागी वर्ष 2017 में अबुधाबी में आयोजित होने वाली द्विवार्षिक विश्व कौशल अंतरराष्ट्रीय

प्रतियोगिता के लिए तैयार किये जा सकें।

राष्ट्रीय श्रम बाजार सूचना केंद्र (एलएमआईएस)

भारतीय कौशल विकास व्यवस्था को बेहतर बनाने और आपूर्ति एवं मांग का सही आकलन करने के लिए यह एक तरह से एकल खिड़की है।

यह वैश्विक मानकों के अनुरूप संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रियाओं, तौर-तरीकों और डेटा रखने की वो समेकित व्यवस्था है, जिससे हमें श्रम बाजार से जुड़ी सभी सूचनायें उपलब्ध हो सकेंगी।

एलएमआइएस के जरिए श्रम बाजार से जुड़ी सांख्यिकी और गैर सांख्यिकी सूचनायें तैयार की जाएंगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान (एनएसडीए) को राष्ट्रीय स्तर पर एलएमआइएस के विकास के लिए प्रमुख संस्था के रूप में निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना

इस महत्वाकांक्षी योजना का बजट 10,000 करोड़ है और इसके माध्यम से साल 2019-20 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह योजना एमएसडीई के प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) की निगरानी में लागू की जाएगी। नियोक्ता, जो इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करेंगे, उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण को कुशल श्रम शक्ति विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नीति 2015 के तहत घोषित उद्देश्य और उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है।

इस नीति का उद्देश्य उद्योग जगत और एमएसएमई के साथ सक्रिय भागीदारी करते हुए साल 2020 तक रोजगार के अवसरों में 10 गुना वृद्धि करने का है।

स्किल इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से कई प्रशिक्षण संस्थानों ने राज्य सरकारों के साथ अधिकतम युवाओं का नामांकन करने के लिए करार किया है

आदर्श संतुलन की स्थापना

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत का अभिप्रेत राष्ट्रीय प्रतिबद्ध अंशदान (आईएनडीसी) एक बहुआयामी और व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत हितधारकों का सम्मेलन (सीओपी) दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक जलवायु परिवर्तन से निबटने की दिशा में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। इसकी कोशिश है कि इस समस्या का सामूहिक वैश्विक हल ढूंढा जाए।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस प्रयास में सार्थक योगदान दिया है। पिछले साल पेरिस में 30 नवंबर और 11 दिसंबर के बीच आयोजित हुए सीओपी 21 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न देशों की राय बनाने में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई और सम्मेलन में मजबूत नेतृत्व बनकर उभरा।

दो हफ्ते के गहन विमर्श के बाद 196 देशों ने अभिप्रेत राष्ट्रीय प्रतिबद्ध अंशदान (आईएनडीसी) पर हस्ताक्षर किये। अभिप्रेत राष्ट्रीय प्रतिबद्ध अंशदान के तहत कार्बन उत्सर्जन में की जाने वाली कटौती को लेकर किये गये इस समझौते को एतिहासिक बताते हुए पूरी दुनिया में इसका स्वागत किया गया। कहा गया कि इसके जरिए पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में मदद मिलेगी। इससे विश्व अर्थव्यवस्था को 2050 के बाद कार्बन निरपेक्ष बनाया जा सकेगा।

इन सभी देशों ने स्वच्छ तकनीक के लिए हर साल 100 अरब डॉलर की राशि देने का वादा किया है। हालांकि इसके लिए विभिन्न देशों की निश्चित जवाबदेही और इसे लागू करने के साधनों का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में भारत ने तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला, इसने सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों (सीबीडीआर) के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए स्वच्छ ईंधन और हरित तकनीक अपनाने पर जोर दिया।

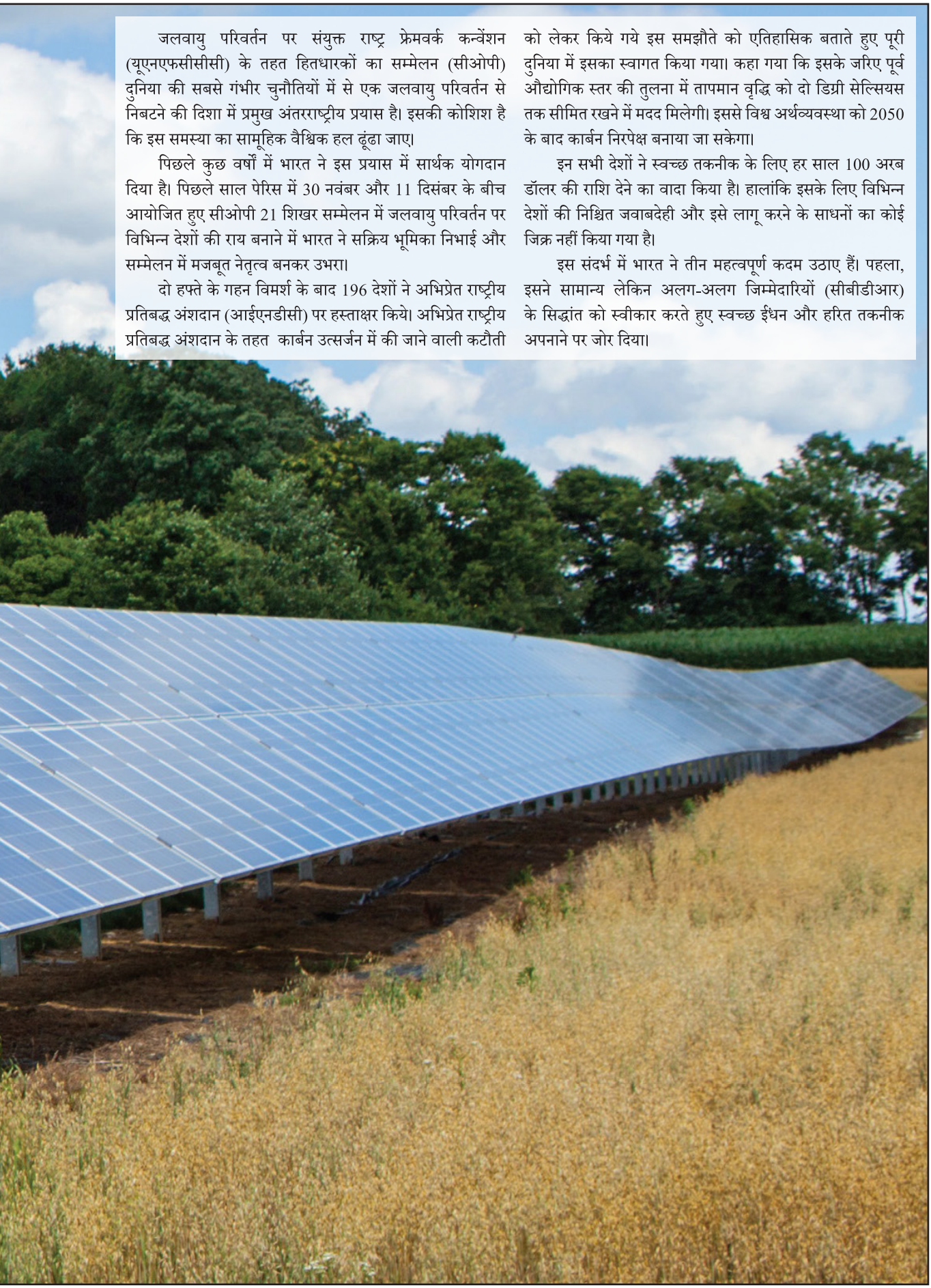

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री प्रकाश जावडेकर नई दिल्ली में आईएनडीसी के संबंध में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

दूसरा, जीवाश्म ईंधन की जगह लेने वाली सस्ती सौर शक्ति की खोज के लिए इसने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया है। इसमें शामिल होने के लिए इसने प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा की उपलब्धता वाले 120 देशों को आमंत्रित किया है। इस गठबंधन की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रेंकोइस होलांदे के साथ की।

जलवायु परिवर्तन: क्यों भारत ने केवल 35 प्रतिशत तक उत्सर्जन तीव्रता ही कम करने का वादा किया

तीन करोड़ डॉलर की लागत से इस गठबंधन का मुख्यालय भारत अपने ही देश में बना रहा है। हालांकि इसकी योजना सदस्यता शुल्क और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से अंतत: 40 करोड़ डॉलर जुटाने की है।

और तीसरा, भारत ने पर्यावरण वित्त में इक्विटी पर जोर दिया ताकि जीवाश्म ईंधन के दम पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन चुके विकसित देश अब विकासशील देशों की आर्थिक मदद करें। इससे सस्ते लेकिन नुकसानदेह ईंधन का इस्तेमाल करने वाले विकासशील देशों को विकसित देशों से हरित तकनीक मिल सकेगी और वे स्वच्छ लेकिन महंगे ईंधन को जल्दी अपना सकेंगे।

यह गठबंधन सुनिश्चित करेगा कि विकासशील देश तीव्रतर आर्थिक विकास के रास्ते पर चल सकें और सतत पर्यावरण अनुकूल तरीके से अपने करोड़ों निवासियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हों।

भारत का आईएनडीसी (अभिप्रेत राष्ट्रीय प्रतिबद्ध अंशदान) लक्ष्य सम्मेलन से पूर्व आवश्यक खाका तैयार कर लेना था, जिसे इसने पिछले साल अक्टूबर में घोषित कर दिया था। इसके लक्ष्य उच्च थे जोकि बातचीत की सफलता में उपयोगी साबित हुए।

आईएनडीसी तीन प्राथमिक प्लेटफार्म पर खड़ा है। पहला, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में कमी, दूसरा, देश की ऊर्जा क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि और तीसरा, वन क्षेत्र में वृद्धि।

पहले मामले में भारत ने 2030 तक अपने जीडीपी के उत्सर्जन घनत्व में 33 से 35 प्रतिशत कमी का वादा किया है। इससे उत्सर्जन स्तर 2005 के पूर्व स्तर पर आ जाएगा।

दूसरे मामले में भारत सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2030 तक उसकी ऊर्जा जरूरतों का कम से कम 40 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा हो।

तीसरे मामले में भारत ने अपने वन क्षेत्र में इतनी वृद्धि का लक्ष्य रखा है कि यह 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड की 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त मात्रा को अवशोषित करने में सक्षम हो।

कुल मिलाकर भारत का आईएनडीसी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक बहुआयामी और व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

उन्होंने नई वैश्विक प्रक्रियाओं में सार्थक योगदान देने की भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की ताकि इससे दुनिया विशेषकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं को तीव्रतर विकास के साथ-साथ न्यून-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर जाने में मदद मिलेगी।

इसरो : केवल सपने ही नहीं उपलब्धियां भी बड़ी

पीएसएलवी अब एक विश्वसनीय, सस्ता और सटीक सैटेलाइट प्रक्षेपक बन चुका है। भारत उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए सस्ता और विश्वसनीय विकल्प तलाश रहे देशों के लिए अब एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की शानदार उपलब्धियां रही हैं। इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की चुनौतियों के बावजूद हमने लंबी दूरी तय की। यदि इन उपलब्धियों का अवलोकन करें तो इनमें मल्टी-सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम स्थापित करना, मिनी अंतरिक्ष शटल शुरू करना और जून, 2016 में एक ही प्रक्षेपण से 20 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित कर इतिहास बनाना शामिल है। इससे भी आगे बढ़ते हुए फरवरी, 2017 में तो भारत ने एक ही प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। बहरहाल हमने अपने चंद्र कार्यकम को नये सिरे से कामयाब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का सोचा है।

22 जून, 2016 को ठीक 9 बजकर 26 मिनट पर पीएसएलवी नामक भारतीय रॉकेट ने बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप से उड़ान भरकर इसरो के लिए इतिहास रच दिया। इस अतिसफल रॉकेट ने एक ही प्रक्षेपण से केवल 26 मिनट में 20 सैटेलाइटों को उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया। यह कोई आसान कार्य नहीं है। इसरो के अध्यक्ष डॉ. एएस किरण कुमार ने इस सफल मिशन का वर्णन 'शानदार ढंग से किया गया काम' कहकर किया।

जून, 2016 के 36वें प्रक्षेपण में पीएसएलवी रॉकेट 320 टन वजनी और 44.4 मीटर यानी 15 मंजिली इमारत जितना ऊंचा था। इस प्रक्षेपण के साथ ही इसरो इस रॉकेट का लगातार 35वां सफल प्रक्षेपण करने में कामयाब रहा। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में इसरो ने एक ही मिशन में 10 उपग्रहों को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

हालांकि 2014 में रूस ने एक ही बार में 37 उपग्रहों को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, पर अब भारत इस दिशा में कहां पीछे रहता! 2017 फरवरी में उसने एक ही प्रक्षेपण में अंतरिक्ष में 104 उपग्रहों को स्थापित कर फिर से विश्व रिकॉर्ड बना डाला।

भारत ने 22 जून,2016 को रिकॉर्ड बनाते हुए 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया

> अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की सफलताओं ने ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण के सारे नियमों को झुठला दिया है। इसरो ने एक के बाद एक जो कामयाबी हासिल की है, वह इस बात का प्रमाण है।

भारत ने लॉन्च किए रिकॉर्ड सैटेलाइट

इस मिशन के जरिए कीर्तिमान गढ़ते हुए इसरो ने जिन 17 विदेशी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजा, उनमें से 13 अमेरिका के और बाकी जर्मनी, इंडोनेशिया और कनाडा के थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री और अंतरिक्ष मामलों के प्रभारी राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, "इन 17 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 10.24 मिलियन यूरो और 4.54 मिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया।"

यह प्रक्षेपण इस मायने में खास रहा कि इससे एक ही प्रक्षेपण में अब तक अमेरिका के सबसे ज्यादा यानी 13 सैटेलाइटों को भेजा गया। इस प्रक्षेपण का दिलचस्प पहलू गूगल के स्वामित्व वाले सैटेलाइट को भेजना भी रहा। दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल की सहयोगी कंपनी कैलिफोर्निया की टेरा बेला ने इस प्रक्षेपण के जरिए 110 किलो वजनी सैटेलाइट 'स्काईसैट जेन-2', जो पृथ्वी पर नजर रखने वाला उच्च तकनीक आधारित सैटेलाइट है, अंतरिक्ष में भेजा। कंपनी का कहना है कि इसका इस्तेमाल नये आविष्कारों के चित्रण के लिए किया जाएगा।

विदेशी ग्राहक लगातार अपने छोटे सैटेलाइटों के प्रक्षेपण के लिए भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भारतीय रॉकेटों से प्रक्षेपण में करीब आधी लागत ही आती है। पीएसएलवी एक विश्वसनीय, सस्ता और सटीक प्रक्षेपण यान है, जिसने सस्ते और विश्वसनीय प्रक्षेपण विकल्प की तलाश कर रहे देशों के लिए भारत को आकर्षक गंतव्य बना दिया है।

अब तक इसरो ने 113 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है, जिसमें से 74 सैटेलाइट 20 विभिन्न देशों के हैं। इसके बदले में इसरो ने देश के लिए 120 मिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया है।

अब इसरो को लग गए पंख!

श्रीहरिकोटा में 23 मई, 2016 की गर्म और उमस भरी सुबह की शांति उस वक्त हलचल में तब्दील हो गई, जब देश के नए रॉकेट से मिनी अंतरिक्ष शटल अंतरिक्ष को रवाना किया। इसके साथ ही इसरो ने इतिहास रच दिया। ऐसा लगा मानो इसरो के पंख उग आए हों। अंतरिक्ष की यह उड़ान अनूठी थी, क्योंकि इसरो ने इसके जरिए स्वदेश में निर्मित 'अंतरिक्ष शटल' का पहली बार प्रक्षेपण किया, जो सफल भी रहा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा, "गतिशीलता और समर्पण के साथ इसरो में हमारे वैज्ञानिकों ने सालों से जो काम किया है, वह असाधारण और बहुत प्रेरणादायी है।"

दुनिया की बड़ी शक्तियों ने बार-बार उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यान का विचार भले ही त्याग दिया है, लेकिन भारतीय इंजीनियरों का मानना है कि कक्षा में सैटेलाइटों के सस्ते प्रक्षेपण का उपाय रॉकेट की रिसाइकलिंग या उसे बार-बार उपयोग में लाना ही है। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि बार-बार उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यान से सैटेलाइटों का प्रक्षेपण खर्च 10 गुना सस्ता होकर मात्र 2000 रुपए रह जाएगा।

इसरो ने इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है

> अब तक इसरो ने 113 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, जिनमें 74 उपग्रह 20 विभिन्न देशों के रहे हैं। इससे इसरो ने अब तक 12 करोड़ डॉलर से अधिक कमाए हैं।

मंगल आर्बिटर मिशन अंतरिक्ष यान में उच्च लाभ एंटीना की तैनाती का परीक्षण चल रहा है

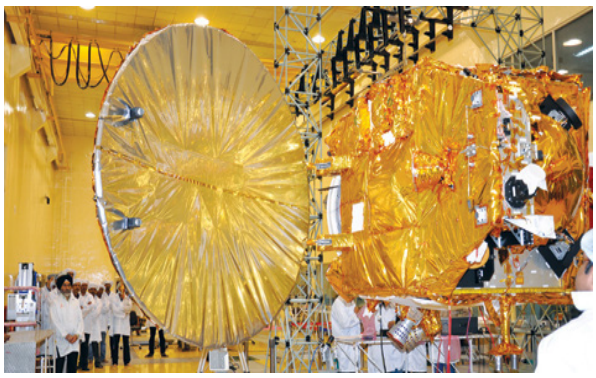

> भारतीय उपग्रहों का समूह तत्काल प्रभाव से पूरे भारतीय क्षेत्र में संचार सिग्नल दिन-रात प्रदान कर रहा है। यह इसरो की एक बड़ी उपलब्धि है।

बार—बार उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यान:

प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (आरएलवी-टीडी) नामक अंतरिक्ष यान को इसरो ने पहली बार प्रक्षेपित किया। इसमें डेल्टा पंख लगे थे। प्रक्षेपण के बाद करीब 13 मिनट की उड़ान के बाद यह बंगाल की खाड़ी के आभासी रनवे पर वापस लौट आया। अब तक केवल अमेरिका ने ही अंतरिक्ष यानों का परिचालन में उपयोग किया है। इसके अंतरिक्ष शटल ने 135 बार उड़ान भरी, पर 2011 में अमेरिका ने इसे हमेशा के लिए सेवा से हटा लिया। रूस ने भी केवल 'बुरान' नामक अंतरिक्ष शटल बनाया। हालांकि इसने केवल एक बार 1989 में उड़ान भरी। इसके बाद फ्रांस और जापान ने भी कुछ प्रयोगात्मक शटल बनाए।

सफलता का संकेत!

हाल ही में इसरो ने तब एक विशेष उपलब्धि हासिल की, जब उसने स्वदेशी संचार तंत्र 'नाविक' विकसित किया। सात उपग्रहों से चलने वाले इस तंत्र का अंतिम उपग्रह 28 अप्रैल, 2016 को पीएसएलवी द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया। यह इसरो की अनूठी उपलब्धि है।

पाकिस्तान से कारगिल की लड़ाई के समय अन्य देशों ने भारत को सैटेलाइट आधारित संचार प्रणाली के बेहतरीन सिग्नल को देने से मना कर दिया था। उस समय हिमालय की चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानियों को मार भगाने के लिए जीपीएस आधारित अत्यंत सटीक सिग्नल की जरूरत थी। तभी से भारत इसे हासिल करने को व्यग्र था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगे बढ़ाया। एनडीए के पहले कार्यकाल में इस स्वदेशी जीपीएस की नींव डाली गई थी, जिसे मोदी जी के कार्यकाल में पूरा किया गया।

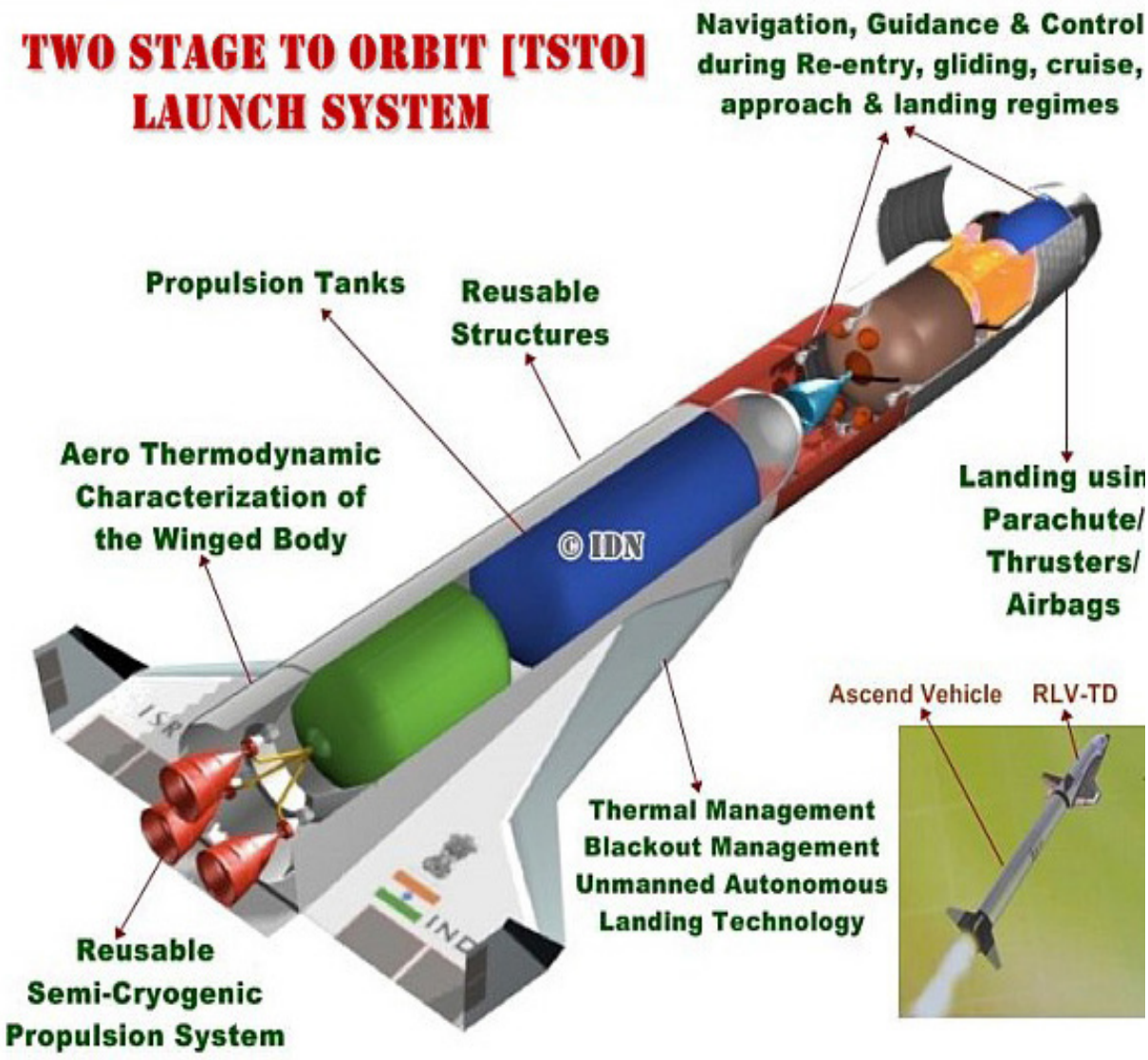

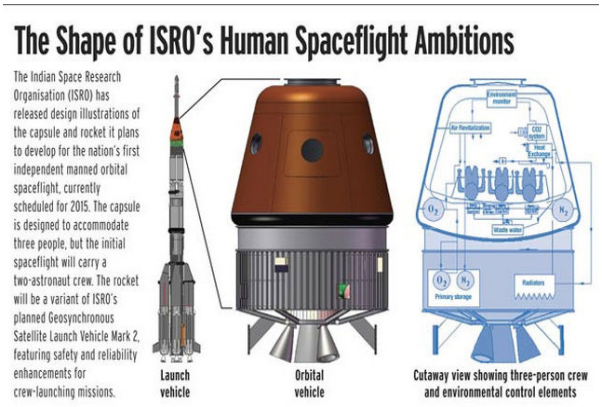

दक्षिण एशिया में उपग्रह आधारित संचार संकेतों को भारत के अलावा अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और रूस का ग्लोनास ही मुहैया करवाता है। इसके अलावा इसरो का यह तंत्र मितव्ययी भी है। इसरो के नाविक को केवल 7 सैटेलाइटों की जरूरत है, वहीं अमेरिका और रूसी तंत्र का दायरा वैश्विक है, जबकि भारत के नाविक की पहुंच केवल दक्षिण एशियाई क्षेत्र तक ही है।

भारत को जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब अतिरिक्त सैटेलाइट जोड़कर अपना दायरा बढ़ा सकता है। नाविक की कवरेज भारतीय सीमाओं के अलावा 1,500 किलोमीटर आगे तक है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की सुरक्षा चिंताएं जहां तक संभावित हैं, वहीं तक इसका दायरा रखा गया है।

इसरो इस साल के अंत में भू-समकालिक सैटेलाइट प्रक्षेपण यान 'मार्क III' का प्रक्षेपण करने की तैयारी में है। पृथ्वी की निचली कक्षा में आठ टन तक के पेलोड ले जाने में यह प्रक्षेपण यान सक्षम होगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो अगले साल भारत चंद्रमा पर अपना दूसरा मिशन 'चंद्रयान-2' भेजेगा। इस मिशन के तहत यान को चंद्रमा पर स्थापित करा भारतीय तिरंगे को सितारों तक पहुंचाया जाएगा।

गुजरात

उड़ान जड़ों से आसमान तक

महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरूषों की धरती गुजरात राज्य भारत का 'वैश्विक आर्थिक सुपर पावर' बनने की ओर अग्रसर है। इसकी पहुंच बंदरगाह वाले सभी बड़े देशों जैसे यूके, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान और खाड़ी देशों आदि तक है। फीजी का गुजरात के साथ महत्वपूर्ण संबंध रहा है। यहां बहुत सारे भारतीय 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में गुजरात आये और इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

गुजरात राज्य को यह नाम गुर्जरों से मिला, जिन्होंने यहां 700-800 ई. में शासन किया था। साबरमती और माही नदी के आसपास फैले प्रागैतिहासिक काल की बस्तियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि इसका समय सिंधू घाटी सभ्यता रहा है, जिसके निशान हड़प्पा केंद्र लोथल, रामपुर, आमरी और अन्य जगहों पर मिले हैं।

बदलाव की बयार : गुजरात श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े बदलाव के दौर से गुजरा है, जो इस बात में भरोसा करते हैं कि 'भारत का भविष्य गुजरात से होकर गुजरता है।' गुजरात अपनी आंतरिक ताकत और असीमित क्षमता की बदौलत भारत को गौरवान्वित करने को संकल्पित है।

> वाईब्रेंट गुजरात सम्मिट एक तरह से गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किया दूरदृष्टि वाला दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत सरकार नीतियों में सामंजस्य और प्रभावी तरीके से निवेश को बढ़ावा देकर समेकित और सतत विकास के लिए बेहतर माहौल बनाती है।

'हरित क्रांति' के मामले में दूसरे स्थान पर : अगर कृषि विकास के आंकड़ों को देखें तो गुजरात ने कृषि विकास दर 9.6 फीसदी तक ले जाने में सफलता पाई और इस तरह से गुजरात ने भारत में कृषि विकास के लिहाज से मिसाल कायम की है। व्यवसायिक स्रोतों से परिपूर्ण गुजरात देश के विकास का इंजन रहा है। यहां निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं, क्योंकि यह देश में औद्योगिक निवेश की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह कई विशिष्ट उद्योगपतियों और महत्वपूर्ण व्यवसायियों की जन्मभूमि भी है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में जेम्स और आभूषण का व्यवसाय यहां तेजी से विकास कर रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात को भारत की 'पेट्रो कैपिटल' भी कहा जाता है। इस राज्य में कुल पेट्रो रसायन उद्योग का 30 फीसदी उत्पादन होता है। रसायन और दवाई के व्यवसाय में गुजरात की हिस्सेदारी 50 फीसदी है। समुद्री उत्पादों, मात्सयिकी और बंदरगाह के लिहाज से गुजरात पहले स्थान पर है। देश में उत्पादित होने वाले कुल सोडा ऐश का 90 फीसदी, नमक का 70 फीसदी और कॉस्टिक सोडा के कुल उत्पादन का 20 फीसदी हिस्सा गुजरात में उत्पादित होता है।

गुजरात में निवेश के अवसर को कई कारक प्रभावित करते हैं जोकि निवेश के बेहतर वातावरण से अभिप्रेरित हैं: गुजरात को विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात एसईजेड नीति-2004 को सबसे पहले लागू करने का सम्मान प्राप्त है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र एक तरह का विकास इंजन है जोकि विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने, निर्यात को तेज करने और रोजगार सृजन में काफी उपयोगी है। एसईजेड एक तरह से शुल्क मुक्त क्षेत्र है और इसका इस्तेमाल व्यापार और उसके परिचालन एवं संवर्धन के लिए विशिष्ट क्षेत्र के रूप में होता है। यह क्षेत्र-कर एवं किसी भी प्रकार के प्रशुल्क से मुक्त होता है।

वाईब्रेंट गुजरात सम्मेलन: वाईब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन की शुरूआत वर्ष 2003 में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गयी। अपने शुरूआती दौर से लेकर अब तक यह देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यवसायिक सम्मेलन बना हुआ है।

वाईब्रेंट गुजरात सम्मिट एक तरह से गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया दूरदृष्टि वाला दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत सरकार नीतियों में सामंजस्य और प्रभावी तरीके से निवेश को बढ़ावा देकर समेकित और सतत विकास के लिए बेहतर माहौल बनाती है। वर्ष 2003 में क्षेत्रीय स्तर पर निवेश मेले के रूप में शुरू हुआ यह द्विवार्षिक सम्मेलन आज विचारों के आदान-प्रदान, ज्ञान के आदान-प्रदान, जुड़ाव, व्यवसायिक अवसरों की खोज और आपसी सहमति और सहभागिता से जुड़े समझौतों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक के लिए नीतिगत कार्यसूची के निर्धारण में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को भी रखा जाता रहा है।

आधारभूत संरचना: गुजरात इस बात पर गर्व कर सकता है कि प्रदेश में देश की सबसे पहली निजी पत्तन परियोजना लगायी गयी। गुजरात में 40 छोटे बंदरगाह हैं, जिनमें से कई निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं और इन बंदरगाहों पर देश के निजी बंदरगाहों का 80 फीसदी माल वहन किया जाता है। एकमात्र रासायनिक बंदरगाह और रस्सी से खिंचा जाने वाला एलएनजी टर्मिनल यहां पीपीपी अर्थात सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के तहत तैयार किया गया है।

शिक्षा: सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिकोण है एसईई (सामाजिक-आर्थिक -शिक्षा) विकास, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा,माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा को जारी रखना, साहित्यिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, फार्मेसी शिक्षा आदि का विकास।

जलवायु परिवर्तन: जलवायु का सही प्रबंधन मानवता के समक्ष बड़ी चुनौती है। इसके नियंत्रण के लिए गुजरात ने जलवायु परिवर्तन का एक अलग विभाग स्थापित किया है।

गुजरात सरकार की यह पहल एक तरह से न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए मानक है, क्योंकि यह एशिया में पहला राज्य है, जहां जलवायु परिवर्तन का विभाग बनाया गया है। इस लिहाज से यह विश्व का चौथा राज्य/सूबा है, जहां जलवायु परिवर्तन के लिए विभाग बनाया गया है।

गुजरात सोलर पार्क

सरकारी योजना

गुजरात सोलर पार्क : भारत को सौर उर्जा का हब बनाना: गुजरात उर्जा निगम लिमिटेड (जीपीसीएल) गुजरात में सौर उर्जा पार्क के विकास के लिए के लिए केंद्रीय एजेंसी है। गुजरात सरकार नवीकरणीय उर्जा के जरिए साफ-सूथरा और हरित उर्जा प्राप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने और सक्रियता से इस दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है।

जीपीसीएल ने एशिया का सबसे बड़ा गुजरात सोलर पार्क बनाया है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके और भावी पीढ़ी को सुरक्षित पर्यावरण दिया जा सके। इसके लिए सौर उर्जा के क्षेत्र को काफी प्रभावकारी और सहजता से अपनाये जाने योग्य बनाया गया है, न सिर्फ भारत के लिए अपितु वैश्विक स्तर पर भी।

इस परियोजना ने पूरे देश के सौर उर्जा परि दृश्य को बदलने में सही मायने में योगदान दिया है। साथ ही यह भारत को विश्व की सौर राजधानी बनाता है और वास्तव में यह गुजरात के लिए काफी गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री निदान योजना : निशुल्क स्वास्थ्य जांच योजना: गुजरात सरकार ने पूरे गुजरात में मुख्यमंत्री निदान योजना की शुरूआत की है। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य जांच और उसके लक्षण की जांच निशुल्क करना है।

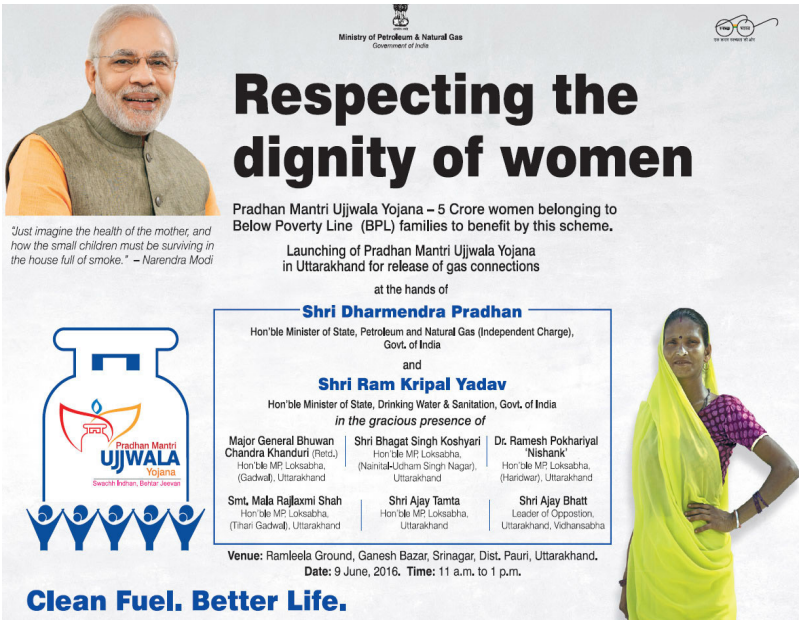

गुजरात में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: पीएमयूवाई उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन दिये जाने के लिए प्रति कनेक्शन 1600 रूपये का वित्तीय सहयोग दे रही है। रसोई के लिए दिये जाने वाले गैस कनेक्शन के जरिए न सिर्फ रसोई तैयार करने के खर्च में कमी आएगी, साथ ही इससे महिलाओं, बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के साथ जंगल भी सुरक्षित रहेंगे।

उजाला गुजरात योजना : गुजरात सरकार ने उर्जा की प्रभाविता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उजाला गुजरात योजना के तहत घरों में बांटे जाने वाले एलइडी बल्ब की कीमत को कम कर दिया है।

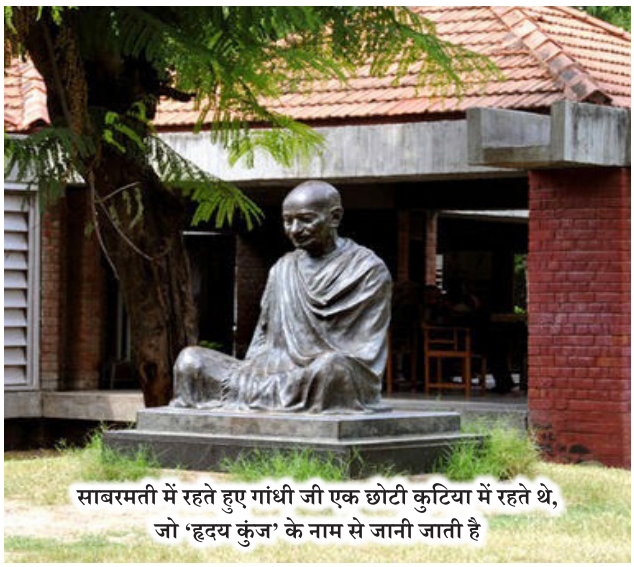

साबरमती में रहते हुए गांधी जी एक छोटी कुटिया में रहते थे, जो 'हृदय कुंज' के नाम से जानी जाती है

महान सोमनाथ मंदिर के अंदर

गुजरात पर्यटन

समय-समय पर गुजरात ने लगातार नृजातीय हमले के साथ ही युद्ध आक्रांताओं के हमलों का सामना किया है, जिन्होंने गुजराती संस्कृति को अपने तरीके से ग्रहण किया। इसका परिणाम यह रहा कि नये विचारों और पुरानी परंपराओं का बेहतर समन्वय तैयार हुआ। बेहतरीन शिल्प, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता, आर्कषण पैदा करने वाला यह राज्य लगातार कलाकारों, ज्ञानियों, बुद्धिजीवियों और व्यवसायियों को पूरे विश्व से आकर्षित करता रहा है।

राज्य के पर्यटक स्थल पूरी तरह आधारभूत संरचनाओं, सुविधाओं और वाणिज्यिक सेवाओं से परिपूर्ण होने के साथ ही संचार, जुड़ाव, अतिथि सत्कार, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि से भी परिपूर्ण हैं।

सोमनाथ मंदिर : सोमनाथ मंदिर की विडंबना रही कि समय-समय पर इसे क्षति का सामना करना पड़ा। इस कारण कई बार इसका विनिर्माण हुआ। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर का निर्माण सोमराज यानी चंद्र देव द्वारा सोने से करवाया गया। इसके बाद रावण द्वारा चांदी से, श्रीकृष्ण द्वारा लकड़ी और भीमदेव द्वारा पत्थर से करवाया गया। इसके बाद भी कई आक्रांताओं द्वारा इस पर हमला किया गया। वर्तमान में जो मंदिर है, उसे 1951 में निर्मित किया गया, जो मौलिक मंदिर की प्रतिकृति है। आज भी अपनी परंपराओं के अनुरूप सूर्यास्त के समय मंदिर के पत्थर का अग्रभाग सोने जैसा प्रतीत होता है।

लक्ष्मी विलास पैलेस: लक्ष्मी विलास पैलेस इंडो-अरबी शैली में बनी असाधारण इमारत है, जिसका निर्माण 1890 में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा कराया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह बर्किंघम पैलेस से चार गुणा बढ़ा है। इसके निर्माण के समय इस महल में वो सारी आधुनिक सुविधाएं जैसे कि लिफ्ट आदि और आंतरिक साज-सज्जा ऐसी थी, जोकि हमें यूरोपिय देशों के बड़े घरों की याद दिलाती है। यह शाही परिवार का आवास बना रहा।

गिर नेशनल पार्क: यह एक राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य है, जोकि 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वन में सूखे पतझड़ वन, बबूल की झाड़ियां, सदाबहार वृक्ष और सदाबहार वनस्पितियों एवं घास के मैदान हैं, जोकि नदियों और धाराओं से घिरे हुए हैं। इस संरक्षित वन में जो प्रमुख जलाशय हैं, उनमें से एक कमलेश्वर डैम है, जोकि मगरमच्छों की बहुतायत के लिए मशहूर है। जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो गिर में लगभग 300 शेर हैं और 300 चीते हैं, जो इसे देश की सबसे बड़ी इस प्रजाति के जानवरों के संघनन स्थल के रूप में पहचान देते हैं।

राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव संरक्षण स्थल का दौरा

भारतीय व अरबी शैली के भवन निर्माण का बेहतरीन नमूना- लक्ष्मी विलास पैलेस

गुजरात का पतंग उत्सव काफी आर्कषक है, जो काफी हर्षोल्लास और आनंदमय तरीके से मनाया जाता है

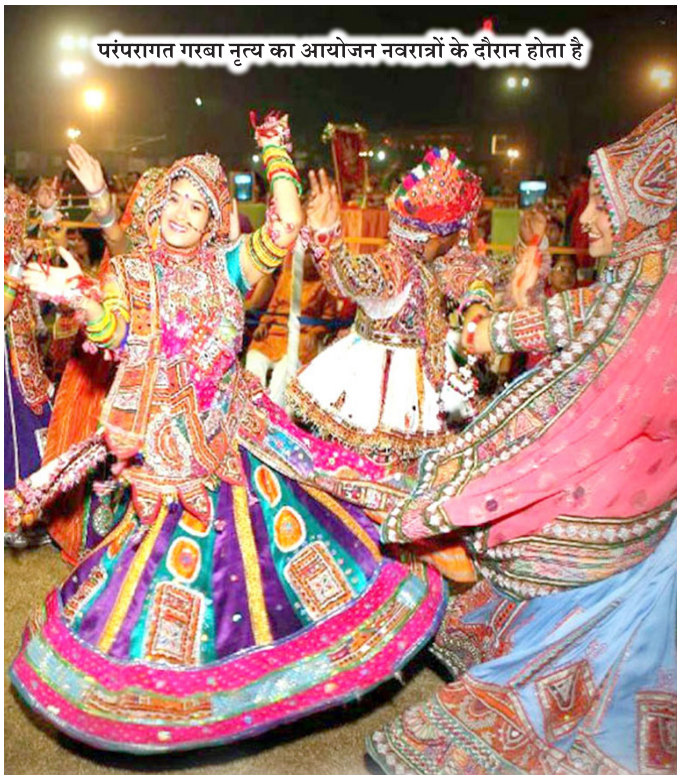

परंपरागत गरबा नृत्य का आयोजन नवरात्रों के दौरान होता है

गुजरात का टिप्पणी लोक नृत्य चौरवाड़ जिले से आया है

गुजराती थाली

गुजराती त्यौहार, मेले और पाकशास्त्र

नवरात्रि: नवरात्रि मतलब है 'नौ रात'। यह भारत के ज्यादातर हिस्सों में मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार है। हालांकि गुजरात एकमात्र राज्य है, जहां नौ दिन तक नृत्य त्यौहार का आयोजन होता है, जोकि विश्व का सबसे बड़ा है।

पतंग उत्सव: मकर संक्रांति को मनाया जाने वाला गुजरात का पतंग उत्सव काफी आकर्षक है। यह काफी हर्षोल्लास और आनंदमय तरीके से मनाया जाता है। पतंगोत्सव गुजरात की सांस्कृतिक ताकत का द्योतक है और गुजरात पतंग की तरह ही आसमान में उड़ान भरते हुए आसमान छूने की इच्छा रखता है अर्थात दुनिया में सबसे बेहतर।

मेला-डांग दरबार: इस मेले के जरिए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान के राजाओं और ग्राम प्रमुख की परंपराओं को सम्मान दिया जाता है। यह परंपरा आदिवासी बहुल जिले डांग में प्रचलित है, जहां कई पूर्व राजाओं और नायकों को आज भी राज्यघरानों की तर्ज पर वही दर्जा प्राप्त है, जिसे समाप्त कर दिया गया था।

खानपान: 'सूरत का जामन और बनारस का मारन' गुजराती की एक प्रसिद्ध कहावत है, जिसका अर्थ हुआ सूरत का खाना और बनारस में मरना स्वर्ग के रास्ते की ओर ले जाता है। गुजरात में यात्रा का एक रोमांचक पहलू वहां के खान-पान की विविधता भी है।

किसी भी राज्य की बेहतरीन संस्कृति को समझने का महत्वपूर्ण जरिया है, वहां के खान-पान की विविधता को समझना। गुजरात इस मामले में काफी समृद्ध है।

परंपरागत गुजराती थाली वहां के खान-पान की परंपरा को समझने का बेहतर जरिया है। एक परंपरागत गुजराती थाली में एक या दो भूने हुए स्नैक्स, जिसे फारसन्स कहा जाता है, एक हरी सब्जी, कंदा या तूंबा का साग (साग सब्जी और मसाले के साथ मिलाकर कढ़ी या मसालेदार सूखा भोजन), एक काठोल (दम देकर पकायी हुई दाल जैसे फली, काबुली चना या सूखा चना), एक या इससे ज्यादा दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे दही, कढ़ी (दही और दाल का सूप), रायता और मीठा व्यंजन, दाल और खिचड़ी। दाल सामान्यत: तूर दाल और मीठा जैसे हलवा, बासुन्डी और श्रीखंड।

इसके साथ ही मीठी, रसदार और मसालेदार चटनी, अंचार, घी और सब्जी का कटा हुआ सलाद या तो सूखा या मसालेदार भी परोसा जाता है।

उत्तर प्रदेश
इंद्रधनुषी धरती

एक नजर में राज्य

> उत्तर प्रदेश को अक्सर यूपी भी कहा जाता है। फीजी के हिंदी बोलने वाले ढेर सारे गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से ही गए थे। फीजी में बोली जाने वाली हिंदी का उत्तर प्रदेश की अवधी,भोजुपरी और खड़ी बोली हिंदी जैसी कई बोलियों से गहरा संबंध है।

गंगा - उत्तर प्रदेश का गौरव

उत्तर प्रदेश की छटा इंद्रधनुषी है। सदियों से यहां विभिन्न संस्कृतियां और भाषाएं पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। भौगोलिक विविधता से परिपूर्ण यहां की जमीन उपजाऊ होने के साथ ही यह राज्य सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक नायकों- राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अशोक, हर्ष, अकबर और महात्मा गांधी की गतिविधियों का केंद्र रहा है।

उत्तर प्रदेश में 'रामलीला' और 'रामायण मंडली' की परंपरा भी प्रदेश को जानने-समझने का एक स्रोत है। दो पौराणिक नदियों गंगा-यमुना के प्रवाह क्षेत्र से सुसज्जित उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के कुल भू-भाग का 9 फीसदी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी कुल जनसंख्या देश की आबादी का 16.4 प्रतिशत है।

ताजमहल : यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। दिल्ली से 180 किमी दूरी पर स्थित ताजमहल विश्व में मानव निर्मित 'सात आश्चर्यों' में प्रथम स्थान रखता है। साहित्य, सिनेमा और कल्पना भी ताजमहल के सौंदर्य और भव्यता को दर्शाने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। यहां तक कि कविता और रोमांस भी ताजमहल के अद्धितीय सौंदर्य को रेखांकित नहीं कर सकते हैं। विश्वगुरु रवींद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के सौंदर्य से अभिभूत होकर इसे 'समय के गाल पर अश्रु की एक बूंद' कहा था।

ताजमहल सफेद संगमरमर का एक चमत्कार है, जो एक युग की संपन्नता को दर्शाता है। इस अद्धितीय संरचना को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1653 ई. में अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल के प्रेम में बनवाया था। आज भी यह इमारत उनके प्रेम की गवाही देते हुए खड़ी है। दुनिया भर से पर्यटक आगरा में ताजमहल देखने आते हैं। भव्य मंदिरों, इमारतों के देश भारत में वास्तुकला का अद्भुत नमूना ताजमहल इन पर्यटकों को भारत की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता से अवगत कराता है।

ताजमहल का अर्थ है 'बादशाह का महल'। यह दुनिया में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और बेजोड़ वास्तुकला वाली सुंदर कब्र है। इस स्मारक को पूरी तरह से तैयार होने में 22 वर्ष और 20,000 श्रमिकों, राजमिस्त्रियों और जौहरियों का श्रम लगा। यह एक सुंदर बगीचे के बीच में स्थित है। फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी की देख-रेख में इसका निर्माण हुआ।

ताज महल

18 अप्रैल, 2016 कोनोएडा (न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने गठन के बाद चार दशक पूरे कर लिये हैं। यह इस बात को सही साबित करता है कि दूरदृष्टि और सुनियोजित योजना के साथ आधारभूत बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की दिशा में कदम बढ़ाया जाये तो अमूमन इसका परिणाम सकारात्मक होता है।

सरकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री और समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य कार्ड: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के निवासियों को न्यूनतम बीमा प्रीमियम राशि पर यह स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5000 सस्ते फ्लैट : राज्य सरकार का आवास विकास बोर्ड यूपीएवीपी या यूपीएचडीबी भी केंद्र सरकार की फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5000 घरों का निर्माण करने की योजना बना रहा है।

'पीएम आवास योजना' केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत गरीबों को सस्ते में घर उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के तहत 2022 तक 20 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

यूपी-100 आपातकालीन सेवा के उद्देश्य : यूपी-100 राज्य-व्यापी आपातकालीन सेवा है, जो चौबीसों घंटे पूरे राज्य में जनता के लिए सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत: बीमा केयर कार्ड : समाजवादी किसान बीमा योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में लगभग 30 लाख परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी।

अर्थव्यवस्था: गेहूं राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसल और गन्ना मुख्य वाणिज्यिक फसल है।

भारत की चीनी का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) राज्य सरकार का एक प्रमुख उपक्रम है, जिसकी भूमिका औद्योगिक संवर्धन और बुनियादी ढांचे के विकास मेंअग्रणीय रही है। राज्य सरकार सन1961 से यूपीएसआईडीसी के माध्यम से औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना और प्रदेश के विकास में लगी है।

यूपीएसआईडीसी की प्रमुख प्रचारात्मक और विकास गतिविधियां निम्न हैं-

(1) बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना।

(2) उद्योग व विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देना,उसकी पहचान करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना।

(3) सरकार के सिविल निर्माण कार्यों में सहयोग और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए डिपॉजिट के आधार पर सुविधा मुहैया कराना।

(4) बड़ी परियोजनाओं के लिए मांग पर भूमि का अधिग्रहण।

(5) एकीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक टाउनशिप का विकास।

एशियन पेंट्स, अरिहंत इंडस्ट्रीज, एवन साइकिल, आत्मा स्टील, अमजुजा एग्रो, बिंदल एग्रो, भूषण स्टील, बीएचईएल, सीईएल, डीसीएम-देवू, डालमिया, दिल्ली प्रेस, एस्कॉर्ट्स, सीएलएएक्सओ,गुडलास, नेरोलैक, हॉकिन्स, हिंदुस्तान लीवर के रूप में प्रतिष्ठित इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स, जेपी इंडस्ट्रीज, जैन ट्यूब, एलएमएल, निरमा, निक्को बैटरी,पाम फार्मा, पेप्सी, पार्ले, रौनक, रेमंड्स, राठी स्टील्स, स्वदेशी पॉलिटेक्स, एसआरएफ, निप्पॉन डेन्सो, शेमकेन मल्टीफेब, सुपर हाउस, सोमैया ऑर्गेनिक्स, टेल्को, टाटा फर्टिलाइजर, वाम ऑर्गेनिक्स, विलियर्ड्स इंडिया, डे मेडिकल्स जैसे प्रतिष्ठत औद्योगिक समूह यूपीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से ही काम कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग फल-फूल रहा है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश-दिल्ली-एनसीआर और लखनऊ-कानपुर गलियारे में। यहां लगभग सभी प्रकार की टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन होता है।

हथकरघा और हस्तशिल्प कुटीर उद्योग पारंपरिक रूप से एक बड़ी संख्या में राज्य के लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं।

सोना, पीतल और वस्त्र

उत्तर प्रदेश अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है

वाराणसी हथकरघा बुनाई और कढ़ाई वस्त्रों का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। जरी-कढ़ाई और सिल्क साड़ियों पर जरी का काम यहां मुख्य तौर पर होता है। लखनऊ 'चिकन' कढ़ाई का एक केंद्र है, यहां की चिकन कढ़ाई की सुंदरता और बारीकी 200 वर्ष से अधिक से प्रसिद्ध है।

राज्य में चमड़ा और चमड़े के उत्पादों के दो प्रमुख उत्पादन केंद्र आगरा और कानपुर हैं। मुरादाबाद पीतल के काम और हस्तशिल्प उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हाल ही में अन्य समानों का भी यहां उत्पादन हो रहा है। यहां के लोहे की चादर के बर्तन, एल्यूमीनियम कलाकृतियां, लकड़ी का काम और कांच के बने सामान विदेशी खरीदारों के लिए लोकप्रिय हो गए हैं। ऐसी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है।

मेरठ एशिया के सबसे बड़े सोने के बाजारों में से एक है। यह खेल से संबंधित वस्तुओं और संगीत वाद्ययंत्रों का देश के अंदर सबसे बड़ा निर्यातक है। बुलंदशहर-खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

नोएडा: न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) एक सुनियोजित, एकीकृत और आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में उभरा है। अच्छी तरह से सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और अति आधुनिक डीएनडी फ्लाईओवर, देश के कुछ हिस्सों से जुड़ा हुआ संपर्क मार्ग इस शहर की विशेषता है।

शिक्षा: उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में 16 विश्वविद्यालय, तीन तकनीकी विश्वविद्यालय, एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (कानपुर), एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (लखनऊ), एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और बड़ी संख्या में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग संस्थान और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये युवाओं की रूचि के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं।

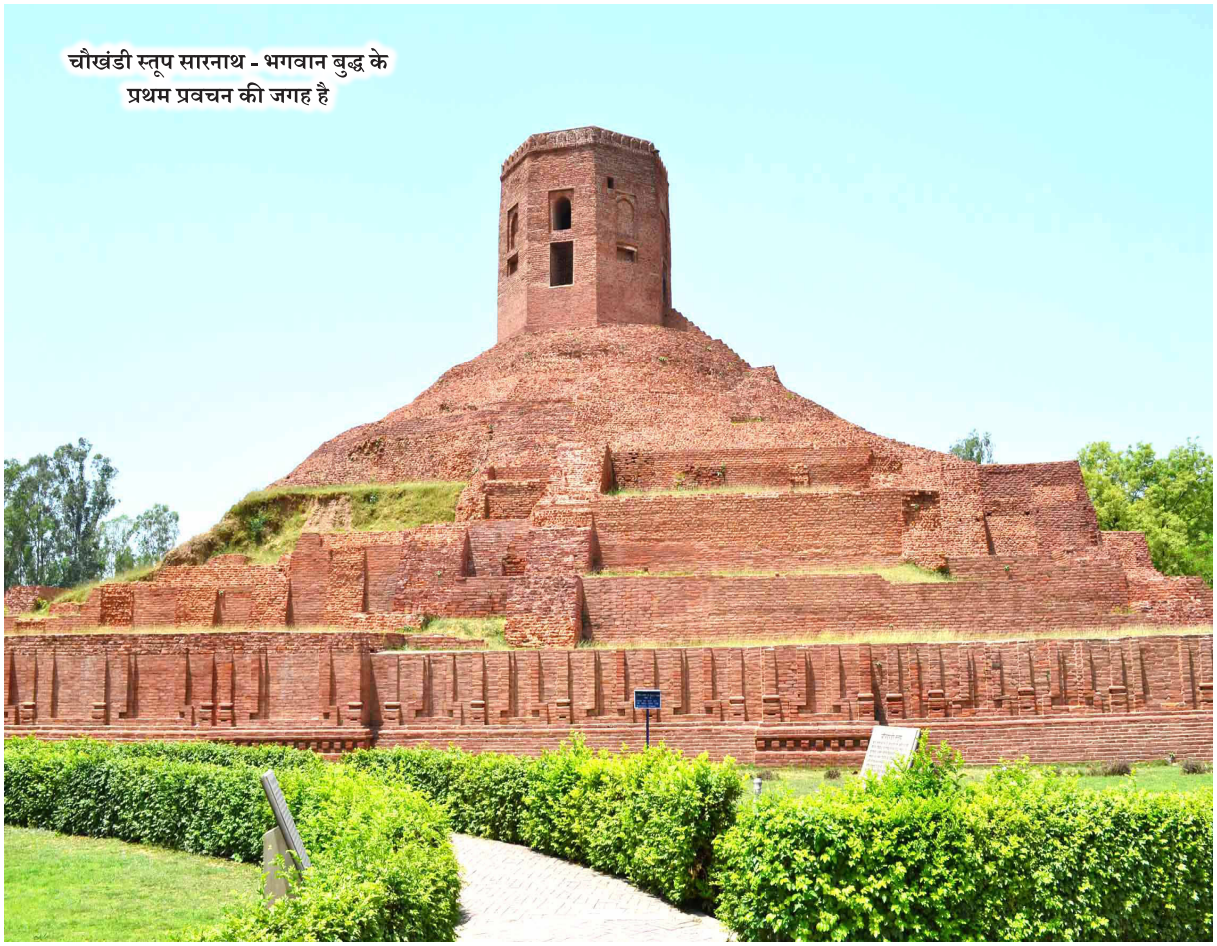
चौखंडी स्तूप सारनाथ - भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की जगह है

आगरा फोर्ट

पर्यटन, संस्कृति और विरासत

यहां के सामाजिक जीवन में संस्कृति पूरी तरह से रची-बसी है। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन उद्गम स्थलों में यह एक है। उत्तर प्रदेश ने मानवता के लिए दो महत्वपूर्ण उपहार 'रामायण' और 'महाभारत' नामक महाकाव्य दिये हैं। महाकाव्य काल से ही उत्तर प्रदेश की धरती ने नव सांस्कृतिक चेतना और धाराओं का पालन-पोषण किया है। उत्तर प्रदेश कई नवीन संस्कृतियों का पालनकर्ता रहा है। हिंदुत्व के साथ ही दो महान चिंतन, जिसमें गौतम बुद्ध और जैनियों के 24 तीर्थंकर महावीर की शिक्षाएं शामिल हैं, ने प्रदेश को काफी प्रभावित किया।

वास्तुकला: उत्तर प्रदेश वास्तुकला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जिसमें बौद्ध स्तूप और विहार, प्राचीन मठ, शहर नियोजन, किले, दरवाजे, महल, मंदिर, मस्जिदें, मकबरें, स्मारक और अन्य सामाजिक भवन शामिल हैं। इसके अलावा तीर्थस्थलों पर और आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, मथुरा, कानपुर, मेरठ और मिर्जापुर जैसे प्रमुख शहरों में मुगल और हिंदू वास्तुकला की शानदार संरचनाएं हैं। इस्लामिक और मध्य एशिया की संस्कृति का प्रभाव भी यहां की वास्तुकला पर परिलक्षित होता है। उत्तर प्रदेश की इस्लामिक इमारतों की भव्यता दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र रही है। प्रदेश के तीन स्मारकों का नाम यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है, जिसमें ताजमहल, आगरा किला और सम्राट अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी शामिल है।

आगरा किला: यूनेस्को विश्व विरासत में स्थान पा चुका आगरा किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। 1565 ईस्वी में अकबर ने इसे अपने कब्जे में लिया। किले के अंदर कई महल मसलन, मोती मस्जिद, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मुसम्मन बुर्ज, जहांगीरी महल, खास महल, शीश महल आदि स्थित हैं।

अयोध्या: भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध अयोध्या लखनऊ से 134 किमी दूर एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। चारों तरफ मंदिरों और मस्जिदों से युक्त फैजाबाद और अयोध्या जुड़वां शहर के रूप में प्रसिद्ध हैं। गंगा-जमुनी स्थापत्य वैभव कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद है। वहीं सरयू के घाट एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करवाते हैं। अवध के नवाब सादात खान ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में नवाब शुजाउद्दौला ने लखनऊ को अवध की राजधानी बनाया।

फतेहपुर सीकरी: आगरा के 37 किलोमीटर पश्चिम की ओर एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित फतेहपुरी सीकरी चार सदी पहले तब अस्तित्व में आया, जब मुगल सम्राट अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। मुगल सम्राट अकबर की उम्र तब 28 वर्ष पूरी नहीं हुई थी, जब अकबर ने भारतीय-इस्लामिक वास्तुकला के तहत इस सुनियोजित शहर की स्थापना की। यह योजना काफी उत्साह से शुरू की गयी थी लेकिन एक दशक बाद इसे छोड़ दिया गया।

हिंदू देवताओं की मूर्ति

मेले, त्यौहार और भोजन

मेले और उत्सव:

उत्तर प्रदेश में लगभग सभी धर्मों के त्यौहार मनाये जाते हैं। यह होली और रामलीला के आयोजन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। हरिद्वार में लगने वाला कुंभ मेला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता के कारण पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। प्रसिद्ध कुंभ मेला इन दोनों का एक अनूठा मिश्रण है। हरिद्वार कुंभ इस सदी के अंतिम कुंभ होने के कारण काफी महत्वपूर्ण है।

भोजन:

अपनी भौगोलिक विविधता की तरह ही उत्तर प्रदेश का भोजन भी कई तरह का है। सब्जियों की तहरी और लखनवी व्यंजन के जायके का तो जवाब ही नहीं है। यहां चाट, समोसे और पकोड़े जैसे व्यंजनों की भी भरमार है। भारत के सभी लोकप्रिय स्ट्रीट फूड चार्ट यहां उपलब्ध हैं। राज्य अपने शाही ढंग से स्वादिष्ट 'नवाबी' भोजन के लिए प्रसिद्ध है।

उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य

उत्तर प्रदेश के आकर्षक व्यंजन

असम

हर ओर हरियाली

असम राज्य को असम चाय और असम रेशम के कारण जाना जाता है। एशिया में प्रथम तेल कुआं यहां खोदा गया था। यह राज्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके एकश्रृंगी गैंडे के साथ ही जलीय भैसों, छोटे सुअरों, एशियाई पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करता है।

यह एशियाई हाथियों के अंतिम बचे हुए कुछ आवास स्थलों में एक है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था को वन्य जीव पर्यटन से सहायता मिलती है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस राष्ट्रीय पार्क में केन्द्रित है। ये विश्व विरासत स्थल भी है।

राज्य में साल वृक्ष के वन हैं, जो वर्षा की अधिकता के कारण पूरे वर्ष हरे रहते हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों की तुलना में असम में वर्षा ज्यादा होती है।

यह वर्षा ब्रह्मपुत्र नदी में पर्याप्त जल आपूर्ति करती है, जिसकी सहायक नदियों और गोखुर झीलों से क्षेत्र को आर्द्र मौसम और सुंदर पर्यावरण उपलब्ध होता है। राज्य के लोग असमी भाषा बोलते हैं। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना में असम की कुल आबादी 31.17 मिलियन थी। असम की अर्थव्यवस्था पहले से ही कृषि प्रधान है। राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 25 प्रतिशत से अधिक है।

राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादों में चावल, चाय, जूट, सरसों, दालें, गन्ना, आलू, संतरा, अनानास, नारियल, सुपारी, कालीमिर्च, खट्टे फल, केला, पपीता, हल्दी, मसाले, फूल, औषधि एवं सुगंधित पौधे हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की सब्जियां राज्य की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सरकारी योजनाएं -

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- शहरी: असम के सभी 97 कस्बों में केन्द्र सरकार की शहरी किफायती आवास योजना को शुरू किया गया है।

अटल अमृत अभियान- असम में स्वास्थ्य बीमा योजना: अटल अमृत अभियान का उद्देश्य राज्य के सभी निवासियों को 2,00000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। अटल अमृत अभियान स्वास्थ्य बीमा योजना में कैंसर, किडनी रोग, मस्तिष्क और हृदय तथा जलने से हुए घावों का इलाज शामिल होगा।

इन रोगों से पीड़ित लोग सभी सरकारी और सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों में 20,000 रुपये तक का इलाज करा सकेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण असम- वर्ष 2017 में 165,000 आवास बनाये जायेंगे। असम में पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को 1,30,000 रुपये की वित्तीय मदद के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये और मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून) के तहत 18,000 रुपये दिये जायेंगे।

आमार आलोही- रूलर होम स्टे स्कीम: असम सरकार ग्रामीण आवास अतिथि ठहराव योजना को राज्य में शीघ्र ही शुरू करने की योजना

चाय उद्योग असम की आत्मा है

असम के चाय उद्योग की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण साख है। भारत के कुल चाय उद्योग क्षेत्रफल का आधा हिस्सा असम में है। असम के चाय उद्योग में औसतन दैनिक 6,00,000 लोगों को राज्य में रोजगार उपलब्ध होता है।

काजीरंगा का सबसे बड़ा आकर्षण - भारतीय गैंडा

बना रही है। योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और अर्द्धशहरी इलाकों में पर्यटन संभावनाओं की तलाश करना है। इस योजना से हजारों रोजगार और आय की संभावनाओं के निर्माण की उम्मीद है। यह योजना पर्यटकों को ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी इलाकों में पर्यटक स्थलों पर आरामदायक ठहराव की सुविधायें उपलब्ध करायेगी।

चाय उद्योग- असम का चाय उद्योग, जो करीब 170 वर्ष पुराना है, राज्य के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असम चाय उद्योग की विश्व अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण साख है। देश के कुल चाय बागानों के क्षेत्रफल का आधा हिस्सा असम में है। असम का चाय उद्योग रोजाना औसतन 60,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, जो देश में औसत मजदूर रोजगार का 50 प्रतिशत है। असम का चाय उद्योग देश में उत्पादित कुल चाय का 50 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करता है।

राज्य में अनुकूल कृषि पर्यावरण के साथ ही पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के कारण बागानी फसलों में रबड़ की खेती भी लोकप्रियता प्राप्त कर रही है।

रेशम उत्पादन असम का एक बड़ा कुटीर उद्योग है। 10,500 से अधिक गांवों में यह कार्य होता है, जिससे हजारों परिवारों को रोजगार प्राप्त होता है। असम का मूंगा नामक सुनहरे रेशम के उत्पादन पर एकाधिकार है और विश्व का 99 प्रतिशत मूंगा रेशम असम में उत्पादित होता है। असम ने मूंगा रेशम में 'भौगोलिक संकेतन' का अधिकार भी हासिल किया है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प- पूर्वोत्तर के राज्य असम में हथकरघा सबसे प्राचीन उद्यमों में से एक है। अपनी समृद्ध बनावट और डिजाइनों के लिए यह व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। इस उद्योग के साथ इतना अधिक महत्व जुड़ा है कि प्रत्येक युवा असमी महिला को विवाह के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए बुनाई का कौशल सीखना अनिवार्य है। पीढ़ियों से चला आ रहा रेशम बुनाई का कौशल असम के लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है।

पर्यटन, संस्कृति और विरासत-

असमी गहने- असम के पास परंपरागत गहनों का एक समृद्ध संग्रह है, जो असम के लिए अनूठा एवं विशिष्ट है। असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोरहाट आभूषण निर्माण का प्रमुख केन्द्र है।

आमार आलोही- ग्रामीण घरों में पर्यटक ठहराव योजना

असम का नौका दौड़ खेल भी एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है

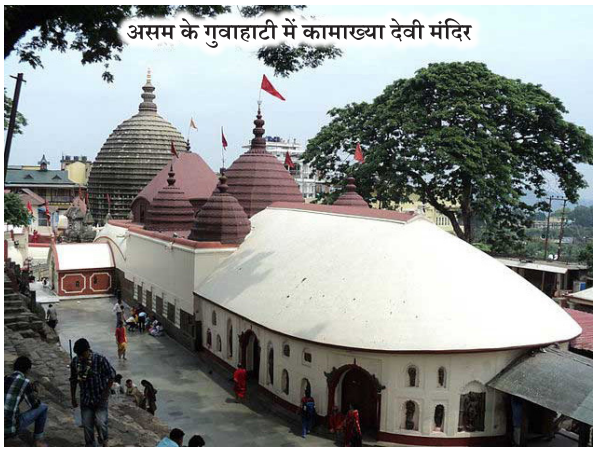
असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर

परंपरागत असमी भोजन

पर्यटन, संस्कृति और विरासत

पर्यटन- ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के साथ एक पक्षी के पंख की तरह विस्तृत असम भारत के पूर्वोत्तर का केंद्रीय राज्य एवं सात राज्यों का प्रवेश द्वार माना जाता है।

गुवाहाटी- पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर और असम के शहरी केंद्रों में प्रमुख यह संपूर्ण क्षेत्र का बड़ा प्रवेश मार्ग है। गुवाहाटी के प्रमुख पर्यटक स्थल कामाख्या मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी पर पानी के जहाज, शंकरदेव कलाक्षेत्र, उमानंदा मंदिर, असम राज्य चिड़ियाघर, शिल्पाग्राम आदि हैं।

काजीरंगा- यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। यह विश्व के सर्वाधिक सुंदर पार्कों में से एक है। यह भारतीय गैंडों के आसान दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या यहां पर 1800 से ज्यादा ही है।

यहां पर बाघों की संख्या भी अधिक है। 2006 में यहां एक टाईगर रिजर्व भी बनाया गया। पार्क का क्षेत्रफल करीब 800 वर्ग किमी. है। यह 1,300 असमी हाथियों का भी आवास है। इसके अलावा यहां 1,800 जंगली भैंसे, 800 दलदली हिरन और 900 पाढ़ा हिरण भी देखने को मिलते हैं। काजीरंगा पक्षी दर्शकों के लिए स्वर्ग की तरह है और इन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के संरक्षक के तौर पर प्रसिद्ध है।

असम का भोजन- परंपरागत असमी भोजन मसालेदार नहीं है। समय के साथ यह मिश्रित होता गया। चावल या भात राज्य के लोगों का प्रमुख भोजन है। वे भात को दाल, मासोर जुल (मछली शोरबा), मांगसो (मांस शोरबा) और शाक या भाजी के साथ खाते हैं। शोरबा आमतौर पर अदरक, लहसुन, इलायची, दालचीनी, प्याज और कभी-कभी नींबू युक्त भी होता है।

असम की संस्कृति- हाल के समय में असमी फिल्मों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। शोषितों और दलितों की दुर्दशा पर जोर देने के साथ ही वे सामाजिक स्थिति का प्रतिबिंब हैं। साहित्य और संगीत यहां की सामाजिक संरचना में घुला-मिला है।

प्राचीनकाल से ही कलाकार एवं मूर्तिकार, राजमिस्त्री एवं वास्तुकार और अन्य हस्त शिल्पी जैसे बुनकर, कुम्हार, सुनार, दस्तकार आदि हाथी दांत, लकड़ी, बास, बेंत और असम में उत्पन्न और अन्य कच्चे माल पर काम करते रहे हैं।

असम के महत्वपूर्ण रेशम उत्पाद इरी, मूंगा और पट हैं।

असम के त्यौहार

असम के त्यौहार मुख्यत: कृषि पर्व हैं, लेकिन उनमें धार्मिक एवं सामाजिक पहलू भी हैं। विभिन्न त्यौहारों एवं परंपराओं से कोई भी असमी लोगों की समृद्ध और सादगी भरी संस्कृति को आसानी से समझ सकता है।

चाय महोत्सव- असम पर्यटन प्रत्येक वर्ष नवंबर में इस त्यौहार का आयोजन करता है। यह अनोखा उत्सव असम के जोरहाट में होता है। जोरहाट चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व की चाय की राजधानी माना जाता है।

अग्निगृह शाश्व त प्रेम का जीवित प्रमाण है

बिहू- बिहू असम का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय त्योहार है। यह राज्य उत्सव है और असम के सभी लोग विशेष गीत एवं नृत्य के साथ इसे मनाते हैं।

तीन प्रकार के बिहू मनाये जाते हैं- भोग बिहू (रंगोली बिहू), काटी बिहू (कांगाली बिहू) और माघ बिहू (भोगाली बिहू)।

अम्बूबाची मेला- यह असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है।

असम के नृत्य -

बिहू नृत्य- यह असम का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बिहू त्यौहार से जुड़ा है। इसे राज्य में खूब धूमधाम और शानदार ढंग से किया जाता है।

खंबा लिम- यह राज्य का विशिष्ट लोक नृत्य है, जिसे दो पंक्तियों में खड़े महिलाओं एवं पुरुषों के समूहों द्वारा संपन्न किया जाता है।

जुमुर नाच- यह राज्य का एक अन्य विशिष्ट नृत्य है, जिसे चाय उद्योग से जुड़े समुदाय द्वारा किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे 'चाय बागान जुमुर नाच' कहा जाता है। लड़के और लड़कियां एक-दूसरे की कमर पकड़कर जुमुर नाच की धुन पर नृत्य करते हैं। इसमें पैरों का सुंदर उपयोग किया जाता है।

असम का बिहू नृत्य

कर्नाटक

वैश्विक परिदृश्य में गंभीरता से उभरता राज्य

कर्नाटक भारत का औद्योगिक रूप से विकसित, संपन्न, नवोन्मेषी और दुनिया की नजर में निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है। कर्नाटक एयरोस्पेस अनुसंधान और विकास के रूप में वैश्विक स्तर पर लोगों को पहली पसंद रहा है। व्यापक अनुभव और एयरोस्पेस में निहित दक्षताओं की वजह से कर्नाटक भारत में बनने वाले विमानों और अंतरिक्ष यानों के निर्माण की एक चौथाई हिस्सेदारी अपने पास रखता है।

अपने अत्यधिक कुशल और प्रतिभाशाली कर्मचारियों, उद्यमशीलता की भावना, भव्य तकनीकी विशेषज्ञता, कठोर निर्णय, सामाजिक बुनियादी ढांचे और एक महानगरीय संस्कृति जैसी विशेषताओं के साथ कर्नाटक व्यापार और निवास के लिए भारत के सभी राज्यों में अव्वल स्थान रखता है।

> कर्नाटक भारत का सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी कलस्टर है।

देश के विकास की गति को बढ़ाने के साथ ही कर्नाटक ने 'ग्लोबल आकर्षण का केंद्र एक राज्य' की टैगलाइन के साथ खुद को स्थापित किया है। वैश्विक तौर पर कर्नाटक की सफलता, व्यापार संचालन और कुशल बुद्धि के लोगों को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए 3 से लेकर 5 फरवरी, 2016 तक चले वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान 'कर्नाटक में निवेश' नाम का एक अभियान चला।

कर्नाटक में निवेश के अवसर आज से पहले इतने आकर्षक कभी नहीं रहे। आज इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, जो भारत की राष्ट्रीय दर से भी अधिक है। यही कारण है कि देश में होने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का चौथा और सबसे बड़ा निवेश कर्नाटक ने पाया है। इसके साथ ही दस कृषि जलवायु क्षेत्रों की उपस्थिति के साथ कर्नाटक के पास देश का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है।

कर्नाटक भारत के सबसे अधिक वैश्विक राज्यों में से एक है। एमआईटी की वैश्विक प्रौद्योगिकी की सूची में कर्नाटक चौथे स्थान पर है। देश के रोजगार क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक के पास देश की चौथी सबसे बड़ी कुशल कर्मियों की फौज है।

इसके अलावा कर्नाटक उद्योग, आईटी, एयरोस्पेस, जैव प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप जैसे रोजगारों की शुरूआत के लिए नीतियां बनाने वाला अग्रणी राज्य है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कर्नाटक भारत का एक प्रमुख राज्य है और विश्व बाजार का चौथा प्रमुख केंद्र है। इसी के चलते कर्नाटक ने सितंबर, 2015 तक औसतन 19.63 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। कर्नाटक के पास 47 सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र, 3 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और समर्पित सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र हैं।

कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। यहां लगभग 123,100 वर्ग किलोमीटर भूमि पर खेती की जाती है, जोकि राज्य के भौगौलिक क्षेत्र का लगभग 64.18 प्रतिशत है। राज्य में मुख्य रूप से नकदी फसलों के तौर पर दाल व तिलहन की खेती होती है और वहीं खाद्य फसल के तौर पर रागी, धान, मक्का, ज्वार, बाजरे की खेती की जाती है।

वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य: कर्नाटक भारतीय उद्योग विशेष रूप से उच्च तकनीकी जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है।

जैव प्रौद्योगिकी: कर्नाटक देश में जैव प्रौद्योगिकी के मामले में सबसे आगे रखा खड़ा दिखाई देता है। वहीं भारत की बायोटेक राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिए विभिन्न संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें बड़ी, छोटी या मध्यम आकार की कंपनियों के साथ ही होनहार स्टार्ट-अप की भी बड़ी संख्या है।

दवा उद्योग: कर्नाटक में दवा उद्योग से जुड़ी 221 निर्माण इकाइयों के साथ-साथ 74 थोक इकाइयां भी हैं और कर्नाटक अपने दवा उत्पादों का 40 प्रतिशत निर्यात करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं फार्मा औद्योगिक क्षेत्रों की बदौलत जीएसके, सिप्ला, हिमालय, माइक्रो लैब्स, केएपीएल, नोवो नोरडिस्क जैसी दवा कंपनियां यहां उपस्थित हैं।

बैंगलुरू की विधानसभा

विकास के पथ पर

सरकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना: इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 150 गांवों को आदर्श गांवों में तब्दील किया जाए।

सुवर्ण कृषि ग्राम योजना या गोल्डन एग्रीकल्चर विलेज स्कीम: कर्नाटक सरकार की इस योजना का लक्ष्य एक साल के अंदर किसानों की आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना था। इस योजना की शुरूआत अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर अर्द्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए की गई है।

मैसूर पैलेस

मुख्यमंत्री सांत्वना हरीश योजना: सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों के इलाज के लिए राज्य सरकार की तरफ से इस योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के तहत सरकार घायल व्यक्ति का शुरूआती 48 घंटों का इलाज नजदीक के ही सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में फ्री उपलब्ध करवाती है।

लैपटाप भाग्य: कर्नाटक सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले समाज के पिछड़े वर्ग के छात्रों को 'लैपटाप भाग्य योजना' के तहत मुफ्त लैपटाप मुहैया कराए जा रहे हैं।

ऑटो और ऑटो उत्पाद उद्योग: कर्नाटक ऑटो उत्पादों के बड़े निर्माताओं में से एक है। कर्नाटक में कुल 5 ऑटो कलस्टर हैं और इसके चलते टोयोटा, वॉल्वो, हॉन्डा स्कैनिया और टीवीएस के साथ डैंसो बॉस्च आदि जैसी एक या दो श्रेणी की कंपनियों की उपस्थिति भी देखी जा सकती है।

कपड़ा उद्योग: कर्नाटक भारत के 65 प्रतिशत कच्चे रेशम, 11 प्रतिशत ऊन के अलावा दूसरा सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक के रूप में अपना योगदान दे रहा है।

कर्नाटक कई बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे नाइक, टॉमी हिलफिगर, एडिडास और ऐलेन सॉली के लिए सोर्सिंग हब भी है।

पर्यटन, संस्कृति और व्यंजन

शिक्षा: कर्नाटक भारत के कुछ प्रमुख शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक और नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है।

पर्यटन: कर्नाटक के पास वैश्विक पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है, जिसमें समुद्र पर्यटन से लेकर डिज्नी थीम पार्क और बंगलुरू में मौजूद स्नोप पार्क जैसे विकल्प भी हैं। कर्नाटक अंतरराष्ट्रीय मानक पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए विकल्प के तौर पर उभर रहा है। केबल कार से लेकर हैली-पर्यटन और एयर चार्टर सेवाएं सभी कुछ यहां उपलब्ध हैं। वहीं बंगलुरू के जक्कर स्थित अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस संग्रहालय, बंगलुरू इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जैसे आकर्षक स्थल भी हैं। ये सभी कर्नाटक को भारत के सबसे बड़े पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करते हैं।

मसाला डोसा- कर्नाटक का पारंपरिक भोजन

राज्य के 319 पर्यटन गंतव्यों की विविधता ने पिछले 5 सालों में अपनी विरासत, वन्य जीवन, आध्यात्मिकता, झरने, नदियों और शहरों की चकाचौंध से 100 लाख से ज्यादा पर्यटकों का मनोरंजन किया है और इसी के चलते पिछले 5 सालों में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।

मैसूर पैलेस: ये महल 1912 में हिंदू और अरबी सुविधाओं के एक संयोजन के साथ भारत-अरबी शैली में बनाया गया था। इसमें विस्तृत और तरह-तरह के तत्व, गोल और थोड़ा नक्काशीदार मेहराब, छतरियां, पतला स्तंभ कोलोनेड, राजपूत शैली में हिंदू वैशिष्ट्य के साथ संगमरमर, मेहराब की नक्काशी, कांच मंडप, दरबार हॉल, पैनल, पक्षियों की तरह की नक्काशियां, पत्ते और होयसल शैली इसे एक मनमोहक महल बनाते हैं।

संस्कृति और व्यंजन: कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ वहां के लोगों की भाषाई विविधता और विभिन्न तरह के धार्मिक रीति-रिवाजों से गहरी जुड़ी हुई है, जिसका कि ऐतिहासिक महत्व है और इसने राज्य की वैविध्य सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने में अतुल्य योगदान दिया।

पारंपरिक लोक कला घुमंतू मंडलियों द्वारा प्रस्तुत संगीत, नृत्य, नाटक, कथा वाचन आदि को अपने में समेटती है। यक्षगान, जिसका उदगम कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों से हुआ, आज कर्नाटक के रंगमंच की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य नाटिकाओं में से एक है।

कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसमें कन्नड़ और हिंदुस्तानी दोनों शैलियां शामिल हैं। भरतनाट्यम के लिए तो कर्नाटक हमेशा से मशहूर रहा है।

त्यौहार: रंग, मस्ती, नाटिका, खुशी, मिठाई, आशीर्वाद, फैंसी पोशाक, शानदार दावतें, ये सभी कर्नाटक में मनाए जाने वाले त्यौहार को सबसे अलग बनाते हैं।

भारतीय उत्सव के माहौल के बीच आप खुद को रोमांचित महसूस करेंगे। कर्नाटक अपनी दिनचर्या के बीच से ही त्यौहारों और मेलों के माध्यम से अपनी परंपराओं को काफी खूबसूरती से संजो रहा है।

भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर, 2014 को सूवा में फीजी की संसद को संबोधित करते हुए

द्विपक्षीय संबंध

भारत और फीजी के बीच 19वीं सदी से ही एक विशेष प्रकार का ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंध रहा है। दोनों देशों के बीच संबंध दिनोंदिन और बेहतर हो रहे हैं। नवंबर, 2014 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की फीजी यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध बहुत ही सकारात्मक हो गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में 2017-2022 की अवधि के लिए जब न्यूयॉर्क में नवंबर, 2016 में चुनाव हुआ तो उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील श्री अनिरुद्ध राजपूत को फीजी ने समर्थन दिया।

भारतीय और फ्रांसीसी पहल पर हो रहे अंतरराष्ट्रीय सौर समझौते के बुनियादी ढांचे पर फीजी ने 15 नवंबर, 2016 को माराकेस, मोरक्को में हस्ताक्षर किए।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फीजी यात्रा के दौरान भारत और फीजी के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए-

(क) फीजी में एक को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए क्रेडिट लाइन का विस्तार।

(ख) राजनयिकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग।

(ग) संबंधित राजधानियों में अपने राजनयिक मिशनों के लिए भूमि का निर्धारण।

इस यात्रा के दौरान फीजी में भारत-प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच (FIPIC) की पहली शिखर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 देशों ने भाग लिया।

मार्च 2016 में भारत की विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज से माननीय श्री अय्याज सैय्यद खय्यूम, फीजी के आर्थिक मामलों के मंत्री एवं अटार्नी जनरल ने नई दिल्ली में मुलाकात की

अक्टूबर, 2013 में भारतीय अंतरिक्ष विभाग और इसरो की ओर से वैज्ञानिक दल का फीजी दौरा और फीजी के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रातू एपेली नाइलातिकाऊ से मुलाकात

फीजी में भारत

मजबूत संबंध

फीजी के प्रधानमंत्री रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) जोसाईआ वौरेंगे बाईनीमारामा ने भारतीय उच्चायुक्त श्री विश्वास सापकाल से सहायता चेक प्राप्त किया

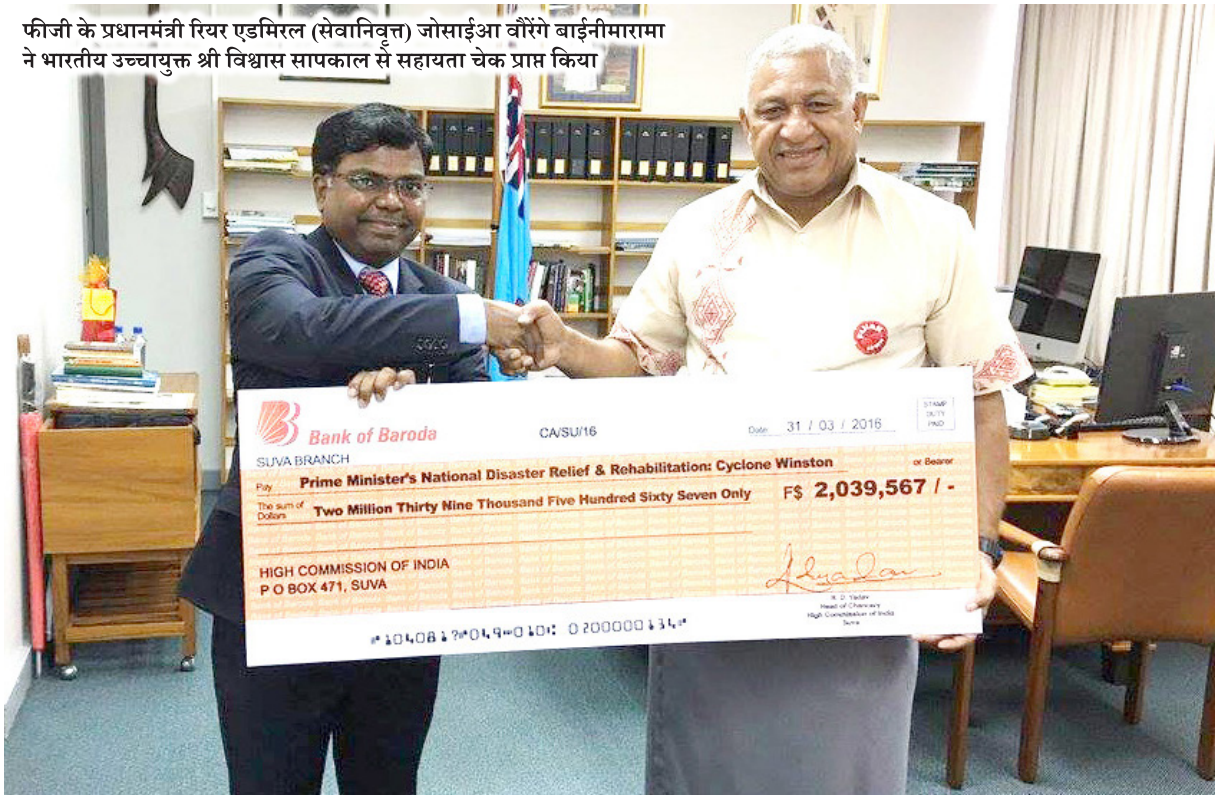

भारत सरकार की तरफ से फीजीयन प्रधानमंत्री राहत कोष को 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर दान में दिए गए। साथ ही फीजी में 2016 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वजह से हुई बर्बादी की भरपाई के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राहत सामग्री भी दी गई

फीजी में चक्रवाती तूफान विंस्टन के गंभीर पीड़ितों के लिए भारतीय वायु सेना ने राहत सामग्री पहुंचाई

27 जून, 2016 को भारतीय उच्चायुक्त ने फीजी के माननीय कृषि मंत्री इनिया सेरूइरातू को खेती में सहायता के लिए 2 महिंद्रा एसयूवी और 2 ट्रैक्टर भी दिए

फीजी के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और अटार्नी जनरल माननीय श्री अय्याज सैयद खय्यूम एवं महिला-बाल विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री माननीय सुश्री रोजी अकबर ने बेयरफुट की प्रौद्योगिकी की सराहना की

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2015 में जयपुर में आयोजित द्वितीय भारत-प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन में भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 14 प्रशांत महासागरीय देशों के 2800 मकानों के सौर विद्युतीकरण योजना को मंजूरी दी। राजस्थान के बेयरफुट कॉलेज द्वारा कार्यान्वित की गई। भारत सरकार की तरफ से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के प्रौद्योगिकी विकास के लिए नादावे,फीजी में सौर मामा के लिए 16 अगस्त, 2016 से एक महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस परियोजना के लिए 14 प्रशांत द्वीपीय देशों को सभी उपकरणों की आपूर्ति भारत सरकार की तरफ से की गई। इन उपकरणों की देख-रेख प्रशिक्षित सौर मामा के द्वारा ही की जाएगी।

भारत - मानव संसाधन विकास में भागीदार
आई.सी.सी.आर - सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार की तरफ से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा चलाए जा रहे छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत फीजी के 30 विद्यार्थियों और तुवालू के 5 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए भारत के 140 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति की पेशकश की जा रही है। पाठ्यक्रमों में लेखा, कृषि विज्ञान, कला, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, मानविकी, हिंदी, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, सूचना प्रौद्योगिकी, भाषा, मास कम्युनिकेशन, चित्रकारी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मूर्तिकला आदि विषय शामिल हैं। (छात्रवृत्ति में चिकित्सा, दंत चिकित्सा और इससे संबंधी पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं।) अधिक जानकारी के लिए देखें- http://www.iccrindia.net/ scholarship.html for further details and to download the application forms.)। आईसीसीआर से मिल रही छात्रवृत्तियों में अंतरराष्ट्रीय/घरेलू हवाई किराए, ट्यूशन फीस, रहने वाले भत्ते और होस्टल आवास खर्च शामिल हैं। छात्रवृत्ति के लिये भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, सूवा आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद साक्षात्कार आयोजित करता है।

पुणे, महाराष्ट्र (भारत) स्थित सिम्बायोसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद फिजियन छात्र

फीजीयन छात्रों ने नई दिल्ली, भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में हिस्सा लिया

आईटीईसी-प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहकारिता

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, जिसे 'आईटैक' के नाम से जाना जाता है, इसे 1964 में भारत सरकार द्वारा एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में सहायता के लिए शुरू किया गया था। आईटैक और एससीएएपी (अफ्रीका कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता) के तहत एशिया, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 156 देशों को भारत के पांच दशकों से अधिक के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व और भारतीय विकास संबंधी अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आईटैक पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग और साझेदारी पर आधारित है। यह लोगों की मांग पर केंद्रित है और विकासशील देशों की जरूरतों का समाधान करता है।

श्री ए. गीतेश शर्मा (तत्कालीन उच्चायुक्त) ने आईटैक दिवस पर संबोधन किया

भारत के उच्चायुक्त श्री विश्वास सपकाल और फीजी के उद्योग, व्यापार और पर्यटन मंत्री माननीय फैयाज कोया ने 21 जून, 2016 को फीजी के लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के लिए 2.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत को जानिए कार्यक्रम

विदेश मंत्रालय द्वारा उन्मुखीकरण योजना के तहत प्रवासी भारतीय युवाओं के लिए भारत में जीवन और प्रगति के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए एक तीन सप्ताह के भारत परिचय (केआईपी) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति के बारे में जागरुकता विकसित की गई।

भारत को जानिये कार्यक्रम में महाराष्ट्र (भारत) के मुख्यमंत्री के साथ फीजी के प्रतिभागी

भारत परिचय कार्यक्रम भारत की यात्रा पर आये छात्रों और भारतीय मूल के युवा पेशेवरों को अपने विचार, उम्मीदों और अनुभवों को साझा और समकालीन भारत के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। एक या दो राज्य सरकारों की साझेदारी से हर साल इस तरह के चार-पांच कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

18 से 30 वर्ष आयु समूह के लगभग 35 भारतीय प्रवासी युवाओं को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए चुना जाता है। चयनित प्रतिभागियों को कार्यक्रम की अवधि के दौरान भारत में पूर्ण सत्कार प्रदान किया जाता है।

इंटरनेशनल एयर टिकट (इकानामी क्लास वायुयान किराया) की कुल लागत का 90 प्रतिशत प्रतिभागियों को दिया जाता है।

3. कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं-

- देश पर प्रस्तुतियां, राजनीतिक प्रक्रिया, विभिन्न क्षेत्रों में विकास
- एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय / कॉलेज / संस्थान में शिक्षकों और छात्रों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श
- औद्योगिक विकास पर प्रस्तुति और कुछ उद्योगों का दौरा
- ग्रामीण जीवन को समझने के लिए एक गांव को दौरा
- भारतीय मीडिया से संपर्क
- गैर-सरकारी संस्थाओं व महिलाओं से जुड़ी संस्थाओं से बातचीत
- ऐतिहासिक महत्व के स्थानों/स्मारकों का दौरा
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना
- योग का प्रचार-प्रसार
- उच्च गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात का कार्यक्रम, जिनमें भारत के राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि शामिल हो सकते हैं।

भारतीय नौसेना पोत- सुमित्रा

फीजी दौरे में आईएनएस सुमित्रा के व्यापक और भव्य स्वागत के लिए फीजी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2015 में जयपुर में भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग के लिए आयोजित शिखर सम्मेलन के मंच से घोषणा की थी कि भारतीय युद्धपोत प्रशांत द्वीप के देशों में सद्भावना दौरा करेंगे। इसी कड़ी में भारतीय जलसेना के गश्ती पोत सुमित्रा ने 26 से 29 अक्टूबर तक फीजी की राजधानी सूवा के तट पर डेरा डाला।

भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने भारतीय और फिजी के झंडे को नौसेना जहाज सुमित्रा पर फहराया

आईएनएस सुमित्रा सरयू श्रेणी के पोतों में चौथा पोत है। यह स्वदेशी डिजाइन पर आधारित भारत के एम.एस. गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित है। 2014 में बेड़े में शामिल किये जाने के बाद से जहाज कई परिचालन कार्यों के लिए तैनात किया गया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है 'ऑपरेशन राहत'। इस जहाज ने 2015 में युद्धग्रस्त यमन से विभिन्न देशों के कर्मियों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी पायी। जहाज की सीमा 6,500 समुद्री मील तक है और यह एक ध्रुव/चेतक हेलीकाप्टर के पोतारोहण करने में सक्षम है।

बंदरगाह पर डेरा डाले जाने के दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने की दिशा में कई योजनाएं बनाई गईं। जिसमें फीजी सरकार और फीजी नौसेना के गणमान्य व्यक्तियों के साथ आधिकारिक बातचीत, स्थानीय जनता के साथ संवाद, भारतीय नौसेना कर्मियों और दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच व्यक्तिगत एवं पेशेवर बातचीत शामिल है। फीजी सरकार, रक्षा मंत्रालय और आरएमएफ बैंड की तरफ से आईएनएस सुमित्रा का भव्य स्वागत किया गया। पोत पर 28 अक्टूबर, 2016 को दीवाली का जश्न भी मनाया गया। इस दौरान फीजी के प्रधानमंत्री, कार्यवाहक राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

फीजी के प्रधानमंत्री (दाएं से दूसरे) भारतीय नौसेना जहाज सुमित्रा पर

भारतीय उच्चायुक्त श्री विश्वास सपकाल ने फीजी के कृषि मंत्री इनिया सेरूईरातू को 1.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सब्जियों के बीज प्रदान किए

अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन

14 अक्टूबर, 2016 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अटार्नी जनरल और फीजी के आर्थिक मामलों के मंत्री श्री अय्याज सैयद खय्यूम ने सूवा सिविक सेंटर, फीजी द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया। 14 से 16 अक्टूबर, 2016 तक सूवा सिविक सेंटर में फीजी सेवाश्रम संघ, भारतीय उच्चायोग, फीजी शिक्षा मंत्रालय, फीजी विरासत और कला ने संयुक्त रूप से पहली बार अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन भारतीय सेवाश्रम संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ही एक हिस्सा था। सम्मेलन का विषय था- रामायण का विश्व के लिए संदेश। 1879 में फीजी की धरती पर गिरमिटियों के जहाज के आने के बाद यह पहला मौका है, जब इस तरह का आयोजन किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ष 1916 में फीजी में आखिरी गिरमिटिया जहाज 'सतलुज 5' आया था, इसलिए इस वर्ष को गिरमिटिया शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अटार्नी जनरल और फीजी के आर्थिक मामलों के मंत्री श्री अय्याज सैयद खय्यूम (बायें-1) 14 अक्टूबर, 2016 को अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए। साथ में हैं स्वामी संयुक्तानंद (बायें-2), शिक्षा मंत्री डॉ. महेंद्र रेड्डी (बायें- 3) और निर्मलाबेन (बायें-4)

इताऊकेई भाषा में रामायण की लघु कथाओं के अनुवाद का प्रकाशन

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

फीजी की राजधानी सूवा में भारतीय उच्चायोग की तरफ से छह प्रशांत द्वीप देशों के 13 स्थानों और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016 मनाया गया।

योग दिवस का कार्यक्रम फीजी के सभी द्वीपों में काफी उत्साह से मनाया गया। उत्सव का प्रमुख बिंदु रहा कि सूवा में भारतीय उच्चायोग ने एक सप्ताह तक सार्वजनिक स्थानों पर योग दिवस का आयोजन किया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के दौरान आम लोगों में योग के विषय में जागरुकता विकसित की गई।

फीजी के राष्ट्रपति महामहिम पूर्व मेजर जनर चोची कोनीऊसी कौनरोते (दायें) व साथ में हैं शिक्षा मंत्री माननीय महेंद्र रेड्डी और श्रम मंत्री चोने उसामाते ध्यान योग करते हुए

लंबासा, फीजी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016 समारोह के दौरान उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया

योग दिवस समारोह के दौरान रोटूमा हाई स्कूल के छात्र

स्कूलों में योग

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016 में प्राइमरी स्कूलों से 18,218 और सेकेंड्री स्कूलों से 12,303 यानी कुल 30,512 छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। इन आयोजनों की सबसे अहम बात रही कि फीजी के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी योग को एक साप्ताहिक कार्यकलाप के रूप में स्कूलों में लागू किया गया।

लेखक मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम - एक शाम हिंदी के नाम

फीजी में हिंदी - चुनौतियां और संभावनाएं

प्रशांत द्वीप के देशों में फीजी एक ऐसा देश है, जहां 37 प्रतिशत भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इताऊकेई और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भी फीजी की राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है।

हिंदी भाषा न सिर्फ गांवों में अपितु शहरों और फीजी के लगभग सभी कोनों/ बाजार स्थानों में बोली जाती है । सन 1935 के बाद से फीजी में 'शांति दूत' के नाम से हिंदी साप्ताहिक अखबार भी प्रकाशित किया जा रहा है।

फीजी में हिंदी साहित्य के विकास के लिए कमला प्रसाद मिश्र, जोगिंदर सिंह कंवल, प्रो. सुब्रमणि आदि लेखकों व कवियों का बड़ा योगदान है।

फीजी में 2000 से अधिक रामायण मंडलियां हैं, जो साप्ताहिक बैठक का आयोजन करती हैं।

यहां रामायण हिंदी सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गयी है। हिंदी भाषा ने फीजी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। यह स्कूलों में भी अनिवार्य भाषा है।

जिन देशों में गिरमिटियां हैं, उनमें फीजी ही ऐसा देश है, जहां हिंदी रोजमर्रा उपयोग की एक जीवित भाषा है।

हिंदी भाषा की गौरवशाली परंपरा को जारी रखने के लिए अगली पीढ़ी भी इस परंपरा का हिस्सा बने, इसके लिये इसे और मजबूत बनाने के प्रयास की आवश्यकता है।

फीजी में हिंदी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये सन 2016 में फीजी में भारतीय उच्चायुक्त श्री विश्वास सपकाल के मार्गदर्शन में काफी महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं।

फीजी में भारतीय उच्चायोग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है कि फीजी की राजधानी सूवा में भारतीय उच्चायोग ने अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन (आईआरसी) का आयोजन किया, जिसमें 8 देशों से 25 से अधिक रामायण विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन फीजी के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने किया। सम्मेलन में रामायण और हिंदी के साथ-साथ देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार व प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' में 30,000 से अधिक छात्रों की भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

स्कूलों में हिंदी को मान्यता

हिंदी की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सटी ऑफ साउथ पैसिफिक को 40000 अमेरिकी डालर का अनुदान

हिंदी प्रतियोगिता के आधार पर 25 दिवसीय भारत यात्रा विजेता फीजी की स्वास्थ्य मंत्री के साथ

विश्व हिंदी दिवस- 2016 के अवसर पर फीजी में हिंदी की प्रमुख प्रतिभाओं को शिक्षा मंत्री माननीय महेंद्र रेड्डी द्वारा सम्मानित किया गया

भारतीय उच्चायुक्त श्री विश्वास सपकाल, फीजी के माननीय शिक्षा मंत्री डॉ. महेंद्र रेड्डी, श्री अरूण गोविल (1980 में रामनंद सागर की रामायण के प्रसिद्ध पात्र) और श्री सुमित टप्पू ने 23 से 25 सितंबर, 2016 के बीच फीजी के सूवा और नादी में आयोजित रामायण का कार्यक्रम, जो आईसीसीआर द्वारा आयोजित किया गया था, में भाग लिया

पिछले दो वर्षों में इस मिशन ने फीजी में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए विशेष प्रयास किया है। इस दिशा में अगस्त, 2015 में भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फीजी से आये 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी उल्लेखनीय रही।

इस पहल को प्रमुखता उस वक्त मिली, जब फीजी उच्चायोग में और उसके बाहर भी हिंदी और विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में इताईकेई समुदाय को भागीदार बनाया गया।

'हिंदी परिषद सूवा', 'हिंदी परिषद पश्चिम' और 'हिंदी लेखक' संगठन तैयार किये गए। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन उन लोगों के सम्मान में किया गया, जिन्होंने फीजी में हिंदी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2016 में श्री भुवन दत्त, श्री नेमानी बइनिवालु और श्री अनूप कुमार को पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय ने फंड के अभाव में हिंदी की पढ़ाई से जुड़े कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया था। हालांकि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर की मदद से यह पाठ्यक्रम फिर से शुरू किया गया है।

संपूर्ण फीजी में बड़ी संख्या में स्कूलों में बड़े पैमाने पर हिंदी लेखन और बोलचाल की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। हिंदी शिक्षकों और हिंदी के नवोदित लेखकों के लिए चार बड़े शहरों और क्रमश: दो स्थानों पर कार्यशाला आयोजित भी की गई।

फीजी के तीनों विश्वविद्यालयों में उच्चायोग द्वारा हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय तौर पर भागीदारी की गई। गिरमिट के इतिहास को लेकर तीनों विश्वविद्यालयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और पहले विजेता को 25 दिनों के भारत दौरे का पुरस्कार दिया गया।

अंतिम गिरमिट जहाज 'सतलुज-V' के पहुंचने के शताब्दी समारोह में हिंदी लेखक श्री जेएस कंवल, प्रो. सुब्रमणि, डॉ. चंद्रा और श्री यूसूफ को सम्मानित किया गया। कुल मिला कर फीजी में हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए फीजी में सकारात्मक माहौल बना है।

'महक' नामक पुस्तक का विमोचन, जिसकी लेखिका श्रीमती उत्तरा गुरदयाल हैं (दाहिने से तीसरे)

प्रधानमंत्री कार्यालय, चीनी उद्योग एवं आव्रजन विभाग में स्थायी सचिव राजदूत योगेश कर्ण का उच्चायुक्त द्वारा स्वागत

प्रशांत महासागर में भारत

भारत सभी 14 प्रशांत द्वीप देशों को 200,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक सहयोग मुहैया करा रहा है। भारत प्रशांत द्वीपीय देशों में सूचना तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (सीईआईटी) स्थापित करेगा और बेयर फूट कॉलेज की मदद से सभी 14 पीआईसीएस देशों के 2800 घरों (प्रत्येक देश में 200 घर) में सौर विद्युतीकरण की फ्लैगशिप परियोजना शुरू कर रहा है, जिसके लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये जाने हैं। इसका मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक सौर उर्जा को बढ़ावा दिया जाना है। भारतीय उच्चायुक्त, सूवा के क्षेत्राधिकार में प्रशांत महासागर के 6 द्वीपीय देश आते है। ये देश हैं- टोंगा, कुक आईलैंण्ड, तुवालु, किरीबास, नाऊरू और वानुवातु।

भारतीय उच्चायुक्त श्री विश्वास सपकाल ने फीजी के राष्ट्रपति महामहिम पूर्व मेजर जनर चोची कोनीऊसी कौनरोते को अपना परिचय पत्र दिया

भारतीय उच्चायुक्त श्री विश्वास सपकाल फीजी के राष्ट्रपति महामहिम पूर्व मेजर जनर चोची कोनीऊसी कौनरोते और उनकी पत्नी के साथ

माननीय अटार्नी जनरल एवं आर्थिक मामलों के मंत्री श्री अय्याज सैय्यद खय्यूम भारतीय उच्चायुक्त के साथ

वानुवातु

ऊर्जा, कोयला, नवीकरणीय उर्जा और खान मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वानुवातु के विदेश मंत्री को चेक भेंट करते हुए

ऊर्जा, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में 13 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 25-26 अक्टूबर, 2016 के बीच वानुवातु की यात्रा की।

18 जून, 2016 को वानुवातु में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था।

वानुवातु में किए गए अपने पहले मंत्री स्तरीय दौरे में उर्जा मंत्री ने 1,90,000 अमेरिकी डॉलर का चेक वानुवातु के विदेश मंत्री को वानुवातु के 76 स्कूलों में सूचना तकनीक से जुड़े औजारों के संरक्षण के लिए दिया।

उर्जा राज्य मंत्री ने वानुवातु को भारत की तरफ से दिये जाने वाले वार्षिक अनुदान के तहत 200,000 अमेरिकी डॉलर के एलईडी बल्ब की आपूर्ति के लिए सहयोग का वादा किया। वानुवातु के विदेश मंत्री और भारतीय ऊर्जा मंत्री के बीच पोर्ट विला, वानुवातू में सूचना तकनीक के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए केंद्र स्थापित करने हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

इसी दौरान वानुवातु सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ ही वानुवातु की सरकार ने साल 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला किया।

कुक आईलैण्ड

18 जून, 2017 को कुक आईलैण्ड में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016 का आयोजन किया गया।

16 नवंबर, 2016 को उच्चायुक्त ने कुक आईलैंण्ड में महारानी के प्रतिनिधि माननीय श्री टॉम मार्सटर्स को परिचय पत्र प्रस्तुत किया

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016 कार्यक्रम का आयोजन 18 जून को मूरी बीच रिसार्ट पर किया गया। अमेरिकी नागरिक योगी माया ने संचालन किया

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन वर्ष 2016 में नाऊरू के सिविक सेंटर में किया गया

नाऊरू

24 जून, 2016 को नाऊरू में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016 का आयोजन किया गया था।

अगस्त, 2016 में श्रीमती शिप्रा गोयल के नेतृत्व में दस सदस्यों वाले बॉलीवुड सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल ने नाऊरू में कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित था।

3 नवंबर, 2016 को न्यूयॉर्क में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विधि परिषद के चुनाव में सदस्यता के लिए भारत के उम्मीदवार अनिरूद्ध राजपूत का सर्मथन नाऊरू ने किया।

इसी बीच सांसद और सहायक मंत्री (विदेश मंत्रालय) माननीय मिल्टन दूबे ने नवंबर, 2016 में माराकेस, मोरक्को में अंतरराष्ट्रीय सौर समझौता करने के लिए दौरा किया था।

किरीबास

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह किरीबास में 18 जून, 2015 को आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य एवं मेडिकल सेवाओं के मंत्री माननीय श्री कोबेबे ताईताई के नेतृत्व में चार सदस्यीय किरीबास प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर आया। 25 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच हुए इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को देखना था।

श्री बानूयेरा बेरिना, राष्ट्रपति के विशेष दूत ने नयी दिल्ली में 2-5 नवंबर, 2016 के बीच पहले एशियान मंत्री स्तरीय आपदा एवं जोखिम प्रबंधन सम्मेलन में शिरकत की।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016 का आयोजन किरीबास तकनीकी संस्थान में किया गया। उपराष्ट्रपति माननीय श्री कौराबी नेनेम (दाहिने) मुख्य अतिथि थे और इन्होंने प्रतिभागियों का नेतृत्व किया

टोंगा

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- 2016 का आयोजन टोंगा में 25 जून, 2016 को किया गया।

श्री पाउला पॉवलु मऊ, सीईओ, अंतरिक्ष विज्ञान, ऊर्जा, सूचना, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और संचार मंत्रालय ने गत नवंबर, 2016 में माराकेस, मोरक्को का दौरा किया और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए।

टोंगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016

तुवालु

25 जून, 2016 को तुवालु में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त विशेष दूत श्री सैमुएल पेनिटल तेओ ने 2-5 नवंबर, 2016 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई मंत्री स्तरीय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सम्मेलन में भाग लिया। वहीं महामहिम, गवर्नर जनरल ने 9-15 नवंबर, 2016 के दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के 17वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। श्री अवाफोआ इराटा, स्थायी सचिव, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस संबंधित करार पर 15 नवंबर, 2016 को मोरक्को में हस्ताक्षर किए।

तुवालु में 25 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- 2016 समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन को सभी प्रतिभागियों से विशेष सराहना मिली और लगभग 110 प्रतिभागियों ने इस आयोजन में भाग लिया

योग प्रेमियों ने तुवालु में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2016 में भाग लिया

1954 से फीजी में

न्यू इंडिया एश्योरेंस (एनआईए) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। एनआईए पिछले 63 सालों से फीजी में सक्रिय रही है और फीजी के निवासियों के समर्थन के कारण आज यह कंपनी शुद्ध प्रीमियम के आधार पर फीजी में सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी बन गई है।

एनआईए को सामान्य बीमा कंपनियों के मुकाबले फीजी में सबसे बड़े शाखा नेटवर्क की कंपनी होने का गौरव हासिल है। इस कंपनी की शाखाएं सूवा, नादी, लौटोका और लबासा आदि क्षेत्रों में भी मौजूद है। फीजी की कुल संपत्ति के लिहाज से देखें तो एनआईए सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी है और इसकी सॉल्वेंसी मार्जिन फीजी आधारित सामान्य बीमा कंपनियों के बीच सबसे अधिक है। एनआईए फीजी में केवल एकमात्र ऐसी सामान्य बीमा कंपनी है, जिसको अमरीकन कंपनी एएम ने सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट रेटिंग प्रदान की है।

एनआईए मुख्यत: संपत्ति, ऑटोमोबाइल और दायित्व बीमा आदि क्षेत्रों के लिए उद्योग घरानों, व्यापारियों, वाणिज्य और बड़े पैमाने पर आम जनता की पहली पसंद रही है।

भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते न्यू इंडिया एश्योरेंस का हमेशा से प्रयास रहा है कि भारतीयों और फीजी जनता के बीच भारतीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिले। फीजी में मौजूद भारतीय उच्चायोग की भी इसमें सक्रिय भागीदारी होती है।

वर्ष 2016 के दौरान एनआईए ने भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित निम्नलिखित गतिविधियों में हिस्सा लिया है:

- 21 फरवरी, 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फिक्की प्रतिनिधियों का फीजी में स्वागत
- 21 जून, 2016 को द्वितीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन
- अक्टूबर, 2016 में अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन
- नवंबर, 2016 में फीजी में गिरमिटियों के आगमन के 100 वर्ष पूरा होने पर जश्न

न्यू इंडिया एश्योरेंस के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री सुभाष मेहता ने 17 नवंबर, 2016 को आईसीसी में आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती उत्सव में अतिथि वक्ता के रूप में भाग लिया।

इसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस ने सक्रिय रूप से वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में एचसीआई के साथ संयुक्त रूप से भाग लिया:

- इंडिया हाउस में आयोजित गणतंत्र दिवस उत्सव
- इंडिया हाउस में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह
- आईसीसी में आयोजित गांधी जयंती उत्सव
- 23 जून, 2016 को आयोजित 125वीं अम्बेडकर जयंती समारोह
- 14 नवंबर, 2016 को आईसीसी में आयोजित हिंदी दिवस समारोह
- इंडिया हाउस में आयोजित दीपावाली उत्सव

न्यू इंडिया एश्योरेंस का हमेशा प्रयास रहता है कि एचसीआई के साथ अपनी गतिविधियों को जोड़कर चले। भविष्य में यह सहयोग और भी सुखद रहे, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।

एनआईए की टीम

> एनआईए पिछले 63 सालों से फीजी में सक्रिय रही है और शुद्ध प्रीमियम के आधार पर फीजी में सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी है। इसके लिए हम पूरे दिल से फीजी निवासियों को धन्यवाद देते हैं।

फीजी दिवस में सहभागिता करने वाली एनआईए टीम

होली उत्सव आयोजन करने वाली एनआईए टीम

भारतीय जीवन बीमा निगम के फीजी में 60 वर्ष हुए पूरे

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसीआई) ने फीजी में अपनी सेवाओं की शुरूआत 1956 में की थी और इस प्रकार अक्टूबर, 2016 में 60 वर्ष पूरे किये।

एलआईसीआई के रूप में प्रचलित भारतीय जीवन बीमा निगम फीजी की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भागीदार रही है और जीवन बीमा के क्षेत्र में बाजार का नेतृत्व करती रही है।

एलआईसीआई का मुख्य कार्यालय सूवा में है और इसका शाखा कार्यालय लाटुका में है। एलआईसीआई ने अपना व्यापारिक कार्यालय लंबासा में रखा है।

एलआईसीआई के पास हर वर्ग के लिए 14 तरह की पॉलिसियां हैं और लगभग 60,000 हजार लोगों ने पॉलिसी ले रखी हैं। इसका सर्वाधिक प्रचलित उत्पाद मनी बैक पॉलिसी और न्यू बूला गोल्ड है, जिसके तहत निशुल्क बीमा कवर किया जाता है और यह पॉलिसी के पूरा होने के बाद भी जारी रहता है।

सेवानिवृत्ति योजना को ध्यान में रखते हुए क्लासिक योजना एक विशिष्ट बीमा है। एलआईसीआई के तहत स्थायी दिव्यांगता लाभ, अंशकालिक बीमा, जोखिम वाली बीमारी से जुड़ा समयावधि बीमा और अंतिम संस्कार के लिए चलाई जा रही पॉलिसियां

विभिन्न बीमा पॉलिसियों के तहत आर्कषक फीचर/अनुवृद्धि रखी गयी है।

फीजी में एलआईसीआई की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके तहत गुजरते वर्ष के साथ सतत रूप से बोनस की राशि बेहतर होती गयी है। इसने पॉलिसी भुगतान के तहत वर्ष 2015 में 37 मिलियन फीजीयन डॉलर भुगतान किया। रेखांकित किये जाने योग्य यह है कि वर्ष 2015 में 10.13 मिलियन फीजीयन डॉलर बोनस घोषित किया गया, जोकि अब तक का सबसे ज्यादा था, और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। एलआईसीआई के पास 560 मिलियन फीजीयन डॉलर (280 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से ज्यादा की परिसंपत्ति है, जिसके जरिए इसने फीजी की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने 500 मिलियन फीजीयन डॉलर से ज्यादा का निवेश फीजी की अर्थव्यवस्था में किया है। अर्थव्यवस्था में ज्यादातर निवेश ढांचागत क्षेत्र में किया गया है।

एलआईसीआई का सतत रूप से यह प्रयास रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो उतने लोगों को सुरक्षा मुहैया करायी जाए और इसके जरिए प्राप्त बचत को ज्यादातर जनता के कल्याण में इस्तेमाल किया जाये।

इन जरूरतों को पूरा करने के लिए एलआईसीआई ढांचागत बौंड में निवेश के जरिए सामाजिक कल्याण और अन्य दूसरे क्षेत्रों जैसे खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अपनी सामाजिक जवाबदेही के तहत बढ़ावा दे रही है।

> भारतीय जीवन बीमा निगम कॉरपोरेशन (एलआईसीआई) ने भारत और फीजी में अपना काम एक ही वर्ष में अर्थात 1956 शुरू किया और इस प्रकार अक्टूबर, 2016 में इसे 60 वर्ष पूरे हो गए।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (फीजी परिचालन) श्री जीबी राजपूत ने 25 हजार फीजी डॉलर का चंदा (7 लाख 90 हजार रुपये) फीजी के प्रधानमंत्री रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) जोसाईआ वॉरेंगे बाईनीमारामा को विंसटन चक्रवाती तूफान के बाद चलाये जा रहे पुनर्वास/ पुनर्संरचना की गतिविधियों के लिए दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा की सूवा शाखा के मुख्य प्रबंधक और अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबंधक एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे

बैंक आफ बड़ौदा : ग्राहकों के लिए उत्तम सुविधा

फीजी में बैंक ऑफ बड़ौदा का परिचालन 5 जुलाई, 1961 को शुरू हुआ। सूवा के मार्क स्ट्रीट में इसकी पहली शाखा खोली गयी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा अपने 95,000 ग्राहकों के लगातार सहयोग और उनके जुड़ाव की बदौलत सतत रूप से बिना किसी रूकावट के पिछले 55 वर्षों से सेवा का संचालन कर रहा है।

पूरे फीजी में अपनी सेवाओं के विस्तार और ग्राहकों के दायरे को बढ़ाने के लिए इसने सभी प्रमुख केंद्रों पर 8 शाखाएं खोली हैं। मसलन सूवा, नादी, लाटुका, बा, नासुरी, लंबासा, सिंगाटोका और राकीराकी। बैंक की समस्त सेवाओं का परिचालन 148 समर्पित बैंक कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत भारत के 9 अधिकारी शामिल हैं। बैंक के पास मजबूत सूचना तकनीकी की सुविधा है, ताकि ग्राहकों को उनकी जरूरतों के अनुरूप सेवा मुहैया कराई जा सके। सभी 8 शाखाएं कोर बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। 8 एटीएम बैंक परिसर में और 8 दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद हैं। बैंक अपने ग्राहकों को दक्षिणी प्रशांत बैंक (बीएसपी) के साथ तकनीकी समायोजन के जरिए ईएफटीपॉस सुविधाएं भी मुहैया कराता है।

> बैंक ऑफ बड़ौदा अपने 95,000 हजार ग्राहकों के लगातार सहयोग और उनके जुड़ाव की बदौलत सतत रूप से बिना किसी रूकावट/अबाधित ढंग से पिछले 55 वर्षों से फीजी में सेवा का संचालन कर रहा है।

कोर बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने का फायदा यह है कि इसके जरिए बैंक अपने ग्राहक को, चाहे उसका खाता 8 बैंक शाखाओं में से किसी में भी क्यों न हो, किसी भी शाखा से खाते के परिचालन और लेन-देने की सुविधा देता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा फीजी के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए 55 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। इस कड़ी में बैंक बड़े व्यावसायिक घरानों, माइक्रोफाइनेंस उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यम, खुदरा व्यापार, विनिर्माण इकाइयों, कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गी पालन आदि संबंधित गतिविधियों के लिए सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा फीजी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ फीजी की सहायता से बैंक ऑफ बड़ौदा समाज के गरीब वर्गों का मार्गदर्शन कर रहा है और उन्हें माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी चला रहा है।

अपने खाता धारकों और साझेदारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ ही बैंक फीजी के लोगों के प्रति अपनी सामाजिक जवाबदेही के निर्वहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधानमंत्री राहत कोष, रामकृष्ण मिशन, फीजी सेवाश्रम संघ और अन्य दूसरे एनजीओ, जो लंबे समय से समाज सेवा के कार्यक्रमों में लगे रहे हैं, को अनुदान देता रहा है। इसके साथ ही कैंसर सोसाइटी के फंड जुटाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करने में भी भूमिका निभाता रहा है।

रग्बी 7 टीम, ग्लोबल फोरम फॉर फाईनेंशियल इनक्लूजन, अनाथालय/अस्पताल/वृद्धाश्रम/स्कूल, विभिन्न तरह के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का आयोजन, हिबिस्कुस त्यौहार, रामायण समारोह, अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन आदि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनके आयोजन में बैंक ऑफ बड़ौदा योगदान दे रहा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिवाली, क्रिसमस, हिंदी दिवस और विश्व महिला दिवस आदि का आयोजन किया, जिसका भारतीय व्यवसायिक समुदाय, राजनयिकों और फीजी में रह रहे प्रवासियों के बीच सकारात्मक माहौल बनाने में अहम योगदान रहा।

बैंक ऑफ बड़ौदा फीजी में भारतीय उच्चायोग और प्रवासी समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करता रहा है। इस बैंक के अधिकारी उस चयनित समूह में शामिल रहे हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के आयोजन, गिरमिट दिवस समारोह के सौ वर्ष पूरा होने और स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में अपनी सेवाएं दी हैं।

जल एवं विद्युत कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (वैपकॉस) का फीजी में आगमन

जल एवं विद्युत कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो फीजी के पूर्वी/मध्य और पश्चिमी शहरी क्षेत्रों में जल और दूषित जल पाइप नेटवर्क के लिए 'डिजाइन और निर्माण अनुबंध' के परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है।

वैपकास के तत्वावधान में जल संसाधन विकास और प्रबंधन अध्ययन, सड़क निर्माण और निगरानी, पुल और घाट परियोजना तथा परिवहन योजना और संपत्ति आदि की निगरानी के क्षेत्र में 38 देशों में परामर्श सेवाएं दी जा रही हैं।

पिछले साल वैपकास ने भारत-अफगानिस्तान मैत्री प्रोजेक्ट 'सलमा डैम' का निमार्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया।

29 जुलाई, 2016 को वैपकास (जल एवं विद्युत कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड) के एक शिष्टमंडल और कृषि, ग्रामीण मंत्रालय और समुद्री विकास एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक की अध्यक्षता फीजी के कृषि मंत्री श्री इनिया सेइउरातो ने की। बैठक में फीजी में भारत के उच्चायुक्त के साथ जल एवं विद्युत कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर.के. गुप्ता भी मौजूद रहे।

WAPCOS Limited
(A Government of India Undertaking)

वैपकास (जल एवं विद्युत कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड) भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो फीजी के पूर्वी/मध्य और पश्चिमी शहरी क्षेत्रों में जल और दूषित जल पाइप नेटवर्क के लिए 'डिजाइन और निर्माण अनुबंध' के परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है।

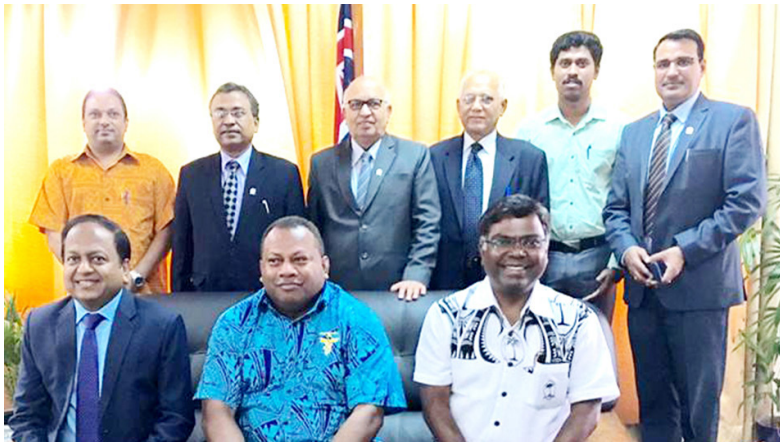

जल एवं विद्युत कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड प्रबंधन ने फीजी के कृषि मंत्री श्री इनिया सेइउरातो के साथ मुलाकात की

सूवा, फीजी में स्टाफ के सदस्यों और परिवार के साथ भारत के उच्चायुक्त

> वैपकास के तत्वावधान में जल संसाधन विकास और प्रबंधन अध्ययन, सड़क निर्माण और निगरानी, पुल और घाट परियोजना तथा परिवहन योजना और संपत्ति आदि की निगरानी के क्षेत्र में 38 देशों में परामर्श सेवाएं दी जा रही हैं।

फीजी में अंतिम गिरमिटिया जहाज के आगमन के शताब्दी समारोह के दौरान गिरमिटिया मूल्य और संस्कृति के प्रसार में योगदान के लिए 12 प्रख्यात भारत-फीजीवासियों का सम्मान।

twitter @HCI_Suva

www.indianhighcommissionfiji.org

facebook @IndiaInFiji

Email: hindi.suva@mea.gov.in

www.indianhighcommissionfiji.org Email: hindi.suva@mea.gov.in